राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 22 नवंबर 2026 वर्ष-9,अंक-287 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

इंस्टाग्राम वीडियो देख ऑर्डर की फेयरनेस क्रीम, हो गई किडनी की गंभीर बीमारी

लड़की कई और दिक्कतों का भी कर रही सामना

मलप्पुरम (एजेंसी)। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को विभिन्न प्रोडक्ट्स प्रमोट करते आपने कई बार देखा होगा। एक ऐसा ही वीडियो देखा केरल के मलप्पुरम में रहने वाली एक 17 वर्षीय लड़की ने और इसके बाद काफी समय तक उनका इस्तेमाल किया। हालांकि उसे वीडियो में प्रमोट किए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस समय यह लड़की गुर्दे की गंभीर बीमारी से जूझ रही है। यह बीमारी कथित तौर पर उसी फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद हुई, जो उसने एक इन्फ्लुएंसर्स द्वारा प्रमोट किए जाने के बाद खरीदी थी। इस लड़की का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने शनिवार को यह जानकारी दी।

मलप्पुरम में एस्टर एमआईएमएस मदर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के अनुसार, लड़की ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशनल वीडियो देखने के बाद वह क्रीम ऑर्डर की। इस वीडियो में दावा किया गया था कि क्रीम से मुंहासे, काले धब्बे और पिगमेंटेशन दूर हो सकते हैं।

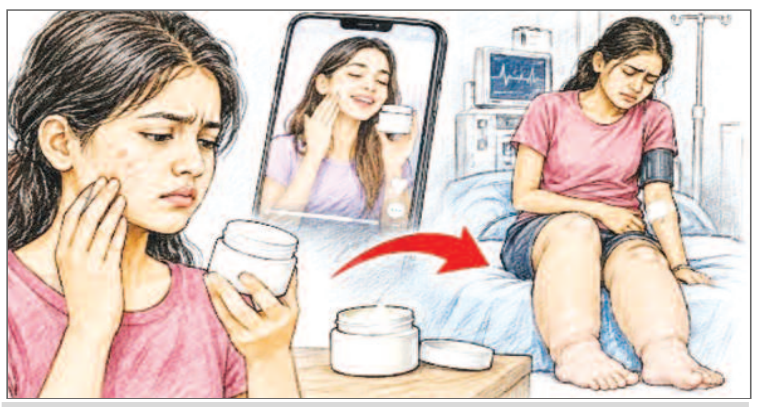

एक साल में कई बोतलें मंगवाईं

लड़की ने पत्रकारों को बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर दिए गए एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए विक्रेताओं से संपर्क किया और प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया। शुरुआत में उसे यह क्रीम असरदार लगी और उसने एक साल के दौरान इसकी कई और बोतलें मंगवाईं। लड़की ने बताया कि बाद में उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगीं, जिनमें अचानक ब्लड प्रेशर गिर जाना और बेहोश हो जाना शामिल था। उसके पैरों में सूजन भी आ गई थी, जिससे उसे चलने-फिरने और सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होने लगी; इसके बाद वह अस्पताल गई।

- **खून में मर्करी की मात्रा अधिक पाई गई-** लड़की का इलाज कर रहीं नेफ्रोलॉजिस्ट गौरी एस. ने पत्रकारों को बताया कि विस्तृत मेडिकल जांच में उसके खून और शरीर में पारे (मर्करी) की खतरनाक रूप से अधिक मात्रा पाई गई है। उन्होंने कहा, पारा किडनी की फिल्टर करने वाली इकाइयों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि लड़की को 'मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी' हो गई है यह किडनी से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज न कराने पर आगे चलकर और भी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। डॉक्टर ने बताया कि क्रीम की जांच में कथित तौर पर 12,500 पार्ट्स प्रति मिलियन पारा (मर्करी) पाया गया, जबकि इसकी सामान्य स्वीकार्य सीमा 1 पीपीएम से भी कम है। उन्होंने कहा कि जांच के नतीजों से पता चलता है कि पारे (मर्करी) वाले इस प्रोडक्ट के कारण ही किडनी की बीमारी हुई।
- **डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेकर ही करें स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल-** नेफ्रोलॉजिस्ट गौरी एस. ने लोगों को ऐसी क्रीमों के विज्ञापनों से सावधान रहने की सलाह दी, जो गोरा करने या त्वचा के रंग में तुरंत सुधार लाने का दावा करती हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें ऐसे उत्पादों पर भरोसा करने के बजाय किसी त्वचा विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) से सलाह लेनी चाहिए और सही इलाज कराना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

भारतीय सैनिक को लगे दुश्मन की गोली तभी मिलेगी पेंशन, ये जरूरी नहीं



नईदिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना से एक जवान से जुड़े पेंशन के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सैनिक भूलवश दुश्मन की गोली लगे बिना भी घायल हो जाता है तो उसे वॉर इंजरी एलिमेंट के तहत पेंशन दी जाएगी। क्या भारतीय सेना के किसी भी जवान को पेंशन तभी मिलनी चाहिए, जब वह दुश्मन की गोली से घायल हो? ये सवाल इसलिए उठा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी घटना को लेकर केस चल रहा था, जिसमें सेना का एक जवान पेंशन की मांग को लेकर अड़ा हुआ था। वह भूलवश अपनी ही बंदूक से चली गोली से घायल हो गया था। इस घटना के बाद वह 40 फीसदी विकलांग हो गया, लेकिन उसे वॉर इंजरी एलिमेंट (युद्ध में लगी चोट) के तहत पेंशन का हकदार नहीं माना गया। जवान इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उसे पेंशन देने का फैसला सुना दिया।

दुर्घटना से लगी चोट का मामला

फैसला सुनाते हुए दो जजों की बेंच ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में सेना के जवानों को वउंडेड बैटल कैजुअल्टी (युद्ध में घायल) माना जाएगा और गंभीर रूप से घायल सैनिक पेंशन पाने का हकदार होगा। आदेश में दो स्थितियों पर विचार किया गया। दुर्घटना से गोली या किसी टुकड़े (स्प्लिंटर) से लगी चोट, या फिर अपने ही सैनिकों की गोलीबारी से लगी चोट। दोनों ही स्थितियों में, यह चोट दुश्मन या उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान लगनी चाहिए। मौजूदा मामला पहले पहलू, यानी दुर्घटना से लगी चोट पर आधारित है।

पेंशन दी जानी चाहिए

युद्ध में लगी चोट के तहत पेंशन पाने के लिए सेना के जवानों का दुश्मन की गोली से घायल होना जरूरी नहीं है। अगर कोई सैनिक किसी ऑपरेशन के दौरान अपनी ही बंदूक से या अपने ही साथियों की गोलीबारी से घायल हो जाता है, तो भी उसे यह पेंशन दी जानी चाहिए।

मणिपुर में जहरीली शराब से 15 की मौत

600 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती; 2026 में 6 राज्यों में 120 से ज्यादा जानें गईं

इंफाल (एजेंसी)। *मणिपुर के चंदेल जिले में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, 600 से ज्यादा लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 2 से 3 दिनों में यह मामला सामने आया है। लोगों की तबीयत शराब पीने के बाद बिगड़ी। हालांकि, शराब कहां से लाई गई थी, इसकी*



पक्की जानकारी उनके पास नहीं है। साल 2026 में जहरीली शराब पीने से मध्यप्रदेश, गुजरात समेत 6 राज्यों में 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री युम्नाम खेमचंद सिंह ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। शिजा अस्पताल के एमडी डॉ. चेतन हुंडोंगबाम के मुताबिक, अस्पताल के सभी बेड भर गए हैं।

शराब में मेथनॉल मिलाने का शक, 10 लोग गिरफ्तार- *पुलिस के मुताबिक, प्रभावित लोगों ने जो शराब पी थी, उसे मणिपुर के काकचिंग जिले के सुगनू से खरीदा गया था। जांच में शराब में मेथनॉल मिलाए जाने की आशंका है। इस मामले में अब तक करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चंदेल जिले में स्थानीय स्तर पर शराब बनाने की कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में आशंका है कि दूसरे इलाकों से शराब लाकर यहां बेची गई थी। पुलिस शराब की सप्लाई करने वालों की तलाश कर रही है।*

देश के कई राज्यों में अब ठंड और कोहरे का असर बढ़ने लगा

यूपी में घना कोहरा, माउंटआबू में तापमान जीरो डिग्री

नई दिल्ली/पटना/जयपुर/ लखनऊ/ भोपाल (एजेंसी)। देश के कई राज्यों में अब ठंड और कोहरे का असर बढ़ने लगा है। यूपी के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई शहरों में घना कोहरा छाया।

- **चक्रवात अकवान से ओडिशा-बंगाल सहित 4 राज्यों में बारिश; दिल्ली में हवा खराब, एक्यूआई 369 पहुंचा**



राजस्थान में भी सर्दी बढ़ रही है। माउंट आबू में शनिवार को तापमान जीरो डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इस कारण ठिठुरन बढ़ गई है। सीकर में पारा 6.5 और जयपुर में 13.3 डिग्री रहा। हालांकि, दिन में गर्मी का असर बना हुआ है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री दर्ज किया गया। चक्रवात अकवान के असर से बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश हो रही है। उधर दिल्ली में शनिवार सुबह हवा की गुणवत्ता यानी एक्यूआई 369 रिकॉर्ड की गई। यह गंभीर कैटेगरी में आती है।

मप्र पहाड़ी बर्फबारी की असर, ठंडक बढ़ी- वहीं पहाड़ों में बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हुई है।

बिहार में पीएम मोदी, गले मिलकर नीतीश कुमार ने किया स्वागत

- **वैशाली में 9.76 किमी लंबे 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन किया**
- **34,470 करोड़ की 227 योजनाओं का शिलान्यास**

हाजीपुर/पटना (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर बिहार के वैशाली में गंगा पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन किया। ब्रिज का नाम बिहार के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखा गया है।

पीएम 21 विभागों की 227 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं की लागत 34,470 करोड़ की से ज्यादा है। पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि पुल का नाम शहीद अक्षयवट राय के नाम पर होना चाहिए।



- ***इस पुल से युवाओं को पढ़ाई और बुजुर्गों को दवाई में आसानी*** *- फसल, दूध-दही को बड़े बाजार में पहुंचाना आसान हो जाएगा। युवाओं को पढ़ाई में और बुजुर्गों को दवाई में बहुत आसान हो जाएगी। आज औरंगाबाद चोरदाहा सिक्स लेन का उद्घाटन हुआ है। आपका प्यार मेरे सिर आंखों पर। मेरे पास कम समय इसलिए बात जल्दी पूरी करनी पड़ेगी। मैंने युवाओं को देखा तो वो तस्वीर मन को प्रसन्न करने वाला था। मेरे बिहार के नौजवानों को विकास की पूरी समझ है। इसीलिए उनमें इतना उत्साह मुझे नजर आ रहा है।*
- ***मेरे मित्र रामविलास जी की आत्मा भी हम पर फूलों की वर्षा करती होगी*** *- मेरे मित्र रामविलास जी की आत्मा भी हम पर फूलों की वर्षा करती होगी। पीएम मोदी ने दिवंगत रामविलास पासवान को मंच से दी श्रद्धांजलि। कहा- ये पुल उनके क्षेत्र के लोगों का सपना था।*

पीएम मोदी ने छठी मइया का नाम लेकर कही बड़ी बात

महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत करके परिवार समाज और जगत का कल्याण किया। छठी मइया के आशीर्वाद से ही हम आज यहां विकास का पर्व मना रहे।

50 साल पहले सेमीकंडक्टर कंपनी का विरोध हुआ: लाल झंडा दिखाया गया, फिर मैंने पहल शुरू की, देश में आज 12 प्लांट

पीएम मोदी ने शनिवार को आईआईटी खड़गपुर में कहा, 'भारत में 50 साल पहले एक कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने आई थी, उसे लाल झंडा दिखाकर रोक दिया गया। सवाल उठे कि



इसकी क्या जरूरत है, यह देश भी बना रहा है वो देश भी बना रहा। हम बनाकर क्या हासिल कर लेंगे।' उन्होंने बताया, मैंने परवाह नहीं की। जब मैं आया तो खुद अफसरों के साथ बैठकर फाइलें तैयार करवाई। आज चार सालों में ढेर सारी सेमीकंडक्टर कंपनियां आई हैं और प्रोडक्शन शुरू किया है। मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली यानी स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर 23 मिनट स्पीच दी।

अरुणाचल में अमित शाह का बड़ा ऐलान

नई न्याय संहिता ला रहे हैं, शीघ्र ही मिलेगा न्याय

ईटानगर (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के बांदेरदेवा पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के परेड ग्राउंड में 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर' प्रदान करने के समारोह में हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस को लोगों और राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवा के सम्मान में प्रतिष्ठित 'प्रेसिडेंट्स कलर' से नवाजा गया। अमित शाह ने कहा कि यह भारत में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो उनकी विशिष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। उन्होंने इसके लिए सभी पुलिसवालों को बधाई दी। अमित शाह ने सियांग प्रोजेक्ट, आतंकवाद और नशा मुक्त भारत की भी बात की।



देश को नशामुक्त बनाने पर काम कर रहे हैं- हम देश को नशामुक्त बनाने पर काम कर रहे हैं। नशा मुक्त अरुणाचल के लिए एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा हूं।

- **2027 के बाद न्याय के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, 3 तीन होगा निपटारा-** पीएम मोदी ने कहा कि जब संसद में विपक्ष पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम मोदी ने क्या किया तो मुझे हंसी आती है। देश के लिए पीएम मोदी की सरकार ने जितना किया है, वह राज्य के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून को हटाकर हमने भारत का कानून लागू किए है। नई न्याय संहिता ला रहे हैं। ऐसा सिस्टम बन रहा है किमें 2027 के बाद जो भी एफआईआर दर्ज होगी, उसका सुप्रीम कोर्ट तक फैसला महज तीन साल में आ जाएगा। लोगों को अब न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी शुरुआत पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी।

मुंबई-हैदराबाद समेत 3 शहरों के मेटा ऑफिस में तोड़फोड़-हंगामा, 4 पर एफआईआर

यूथ कांग्रेस बोली- भाजपा के कहने पर नेताओं के अकाउंट सस्पेंड किए

मुंबई/हैदराबाद/मुंबई (एजेंसी)। हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में मेटा के ऑफिसों के बाहर प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस ने शनिवार को यूथ कांग्रेस के चार नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूथ कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड किए जाने के खिलाफ तीन शहरों में मेटा ऑफिसों के बाहर प्रदर्शन किया था।

हैदराबाद में प्रदर्शनकारी मेटा ऑफिस के अंदर घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। मुंबई में प्रदर्शन के दौरान बिल्डिंग के शीशे पर 'आरएसएस का बेटा मेटा' लिखा गया। वहीं, गुरुग्राम में प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगा दिया। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर मेटा ने 19 नवंबर को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिए थे। संगठन ने मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसका कहना है कि अगर इस दौरान विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट पर लगी पाबंदियां नहीं हटाई गईं तो देशभर में मेटा ऑफिसों के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे।

पंचतत्व में विलीन हुईं सीएम योगी की मां सावित्री देवी

- *भीगी आंखों से दी हरिद्वार के चंडी घाट पर अंतिम विदाई*



हरिद्वार (एजेंसी)। सीएम योगी की मां सावित्री देवी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। हरिद्वार के चंडी घाट में पूरी रस्मों के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इसके बाद मुखाग्नि दी गई। इस दौरान सीएम योगी कई बार भावुक हो गए और आंखों से आंसू को नहीं रोक पाए। हरिद्वार के चंडी घाट में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैशव प्रसाद मौर्य, योग गुरू बाबा रामदेव, गोरखपुर सांसद रवि किशन समेत कई संत और हस्तियां मौजूद रहे।

ट्रम्प बोले-भारत में ब्याज दरें कम, इसलिए 7 प्रतिशत विकास दर



वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की 7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का उदाहरण देकर अपने देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि भारत में ब्याज दरें कम हैं, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं तो वहां की ग्रोथ 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने कहा कि जब भी अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अच्छे आते हैं तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है। जबकि ऐसे समय में दरें कम होनी चाहिए, ताकि कारोबार और निवेश को बढ़ावा मिले।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारत को मिलेगी बुलेट ट्रेन की उड़ान, विकास के नए युग का होगा सूत्रपात

(लेखक - विनोद सिंह 'तकियावाला')

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना ले रही है आकार; रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के विजन, जापानी तकनीक और भारतीय इंजीनियरों के कौशल से विकसित हो रहा देश का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, 2027 में पहली सेवा शुरू करने का लक्ष्य

भारत की विकास यात्रा में कुछ परियोजनाएँ केवल परिवहन का माध्यम नहीं बनतीं, बल्कि वे देश की तकनीकी क्षमता, आर्थिक महत्वाकांक्षा और भविष्य की दिशा का प्रतीक बन जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना ऐसी ही एक ऐतिहासिक पहल है। देश में पहली बार बुलेट ट्रेन का सपना अब धरातल पर आकार ले रहा है। यह परियोजना केवल मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग, औद्योगिक विकास, रोजगार, पर्यटन, निवेश और आत्मनिर्भर भारत की संभावनाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अक्टूबर 2026 को अपने विस्तृत आलेख 'इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज टेकिंग शेप' में इस परियोजना की प्रगति, तकनीकी विशेषताओं और भविष्य की योजनाओं का उल्लेख किया है। उनके प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि भारत का पहला हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर अब केवल घोषणा नहीं, बल्कि विशाल निर्माण कार्य, आधुनिक तकनीक और भारतीय श्रम-कौशल के समन्वय से वास्तविकता बन रहा है। प्रधानमंत्री की विकास परिकल्पना को आगे बढ़ाने में रेल मंत्री का तकनीकी दृष्टिकोण और परियोजना के क्रियान्वयन की गति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

दो महानगर नहीं, एक व्यापक आर्थिक क्षेत्र

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और केंद्रशासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली से होकर गुजरेगा। मार्ग पर मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती सहित 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति है। ट्रेन की डिजाइन गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा लगभग एक घंटा 58 मिनट में पूरी करने की परिकल्पना है, जबकि सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में सामान्यतः आठ से नौ घंटे लग जाते हैं।

इस बदलाव का वास्तविक महत्व समय की बचत से कहीं आगे है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जबकि अहमदाबाद और गुजरात का औद्योगिक क्षेत्र व्यापार, वस्त्र, हीरा, रसायन और विनिर्माण गतिविधियों का बड़ा केंद्र है। इनके बीच तेज और विश्वसनीय संपर्क से कारोबारी यात्राएँ आसान होंगी। सूरत, वडोदरा, आणंद और ठाणे जैसे शहरों को भी इसका लाभ मिलेगा। विद्यार्थी, पेशेवर, उद्यमी और पर्यटक कम समय में लंबी दूरी तय कर सकेंगे। इससे विभिन्न शहरों के बीच रोजगार, निवेश और व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हो सकता है। जापान की हाई-स्पीड रेल व्यवस्था का अनुभव भी यही बताता है कि तेज रेल संपर्क अलग-अलग शहरों की अर्थव्यवस्थाओं को एक-दूसरे के निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आसमान में दौड़ता आधुनिक रेल कॉरिडोर

इस परियोजना का लगभग 465 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड वायाडक्ट पर बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रेल मार्ग को सामान्य सड़क यातायात, समपार फाटकों, पशुओं और अनधिकृत आवाजाही से अलग रखना है। इससे ट्रेन को उच्च गति से सुरक्षित परिचालन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी। रेल मंत्री के अनुसार, सितंबर 2026 तक 456 किलोमीटर पियर निर्माण और 371 किलोमीटर वायाडक्ट निर्माण पूरा हो चुका था। लगभग 299 किलोमीटर हिस्से में छह लाख से अधिक शोर अवरोधक लगाए गए थे। वहीं, 206 किलोमीटर वायाडक्ट पर 9,300 से अधिक ओवरहेड विद्युतीकरण मस्तूल स्थापित किए जा चुके थे।चार पर्वतीय सुरंगों की खुदाई भी पूरी हो चुकी थी। परियोजना के आठ स्टेशनों पर सिविल निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वास्तुशिल्प संबंधी अंतिम कार्य आगे बढ़ रहा था। ये उपलब्धियाँ इस विशाल परियोजना के निर्माण की व्यापकता और तकनीकी जटिलता को दर्शाती हैं।

समुद्र के नीचे सुरंग, इंजीनियरिंग का असाधारण उदाहरण

इस परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण और आकर्षक हिस्सा महाराष्ट्र में बनने वाली लगभग 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग है। इसमें करीब सात किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे समुद्र के भीतर से गुजरेगा। यह भारत की पहली समुद्र के नीचे बनने वाली रेल सुरंग होगी। इसके निर्माण में अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रत्येक मशीन का कटरहेड 13.6 मीटर व्यास का है और मशीन का वजन तीन हजार टन से अधिक है। जुलाई 2026 में इन विशाल मशीनों को निर्माण कार्य में लगाया गया। इनके माध्यम से कठोर चट्टानों को काटकर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है।

मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लगभग 32 मीटर जमीन के नीचे एक भूमिगत स्टेशन भी विकसित किया जा रहा है। यह करीब दस मंजिला इमारत की गहराई के बराबर है। घनी आबादी वाले व्यावसायिक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के सहारे इतने विशाल स्टेशन का निर्माण भारतीय इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहां प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं और तकनीकी सेवाओं के लिए अलग-अलग स्तर बनाए जा रहे हैं।

जापानी तकनीक और भारतीय आत्मनिर्भरता का संगम

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत और जापान के तकनीकी सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसकी आधारशिला रखी थी। जापान की शिंकानसेन तकनीक और वित्तीय सहयोग से शुरू हुई इस परियोजना में अब भारतीय इंजीनियरों, तकनीशियनों और निर्माण कंपनियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड है। इसके अंतर्गत लगभग 40 मीटर लंबा और 970 टन वजनी कंक्रीट गर्डर कारखाने में तैयार किया जाता है और विशेष मशीनों की सहायता से निर्धारित स्थान पर स्थापित किया जाता है। इससे निर्माण की गति और गुणवत्ता दोनों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। शुरुआती चरण में आयात की गई भारी मशीनों के डिजाइन और निर्माण में भी भारतीय इंजीनियरों ने अपनी क्षमता विकसित की है। आज एक हजार टन से अधिक भार उठाने वाली विशाल निर्माण मशीनों का स्वदेश में डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है।

इसी तरह भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्टरी और बीईएमएल के सहयोग से स्वदेशी हाई-स्पीड ट्रेनसेट विकसित किए जा रहे हैं। बी-28 ट्रेनसेट का पहला बॉडी फ्रेम तैयार हो चुका है और उसका संरचनात्मक परीक्षण चल रहा है। इसकी डिजाइन गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके बाद 350 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति वाले बी-35 ट्रेनसेट की दिशा में आगे बढ़ने की योजना है। हाई-स्पीड रेल के लिए आवश्यक ट्रैक, विद्युतीकरण और अन्य तकनीकी उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना भी इसी प्रयास का हिस्सा है। इसका दीर्घकालिक लाभ यह होगा कि भारत केवल विदेशी तकनीक का उपयोग करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उसके निर्माण, रखरखाव और विकास में भी अपनी क्षमता स्थापित कर सकेगा।

सुरक्षा और विद्युतीकरण की अत्याधुनिक व्यवस्था

320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन के लिए सामान्य रेल व्यवस्था से कहीं अधिक उन्नत सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस कॉरिडोर में 28 भूकंपीय सेंसर लगाने की योजना है। भूकंप की प्राथमिक तरंगों का पता लगते ही बिजली आपूर्ति बंद करने और ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोकने की स्वचालित व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके अलावा 14 स्थानों पर हवा की गति मापने वाले उपकरण और संवेदनशील क्षेत्रों में वर्षा मापक यंत्र लगाए जाएंगे। इनसे प्राप्त सूचनाएँ केंद्रीय परिचालन नियंत्रण केंद्र तक पहुंचेंगी, जहां से सुरक्षा संबंधी निर्णय लिए जाएंगे। उच्च गति पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2म25 केवी ओवरहेड विद्युतीकरण प्रणाली अपनाई जा रही है। यह भारत में पहली बार इस स्तर पर इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक रेल विद्युतीकरण तकनीक है। लगभग 22 हजार स्टील मस्तूल पूरे कॉरिडोर में विद्युत नेटवर्क को सहारा देंगे। इस दिशा में 20 नवंबर 2026 की तारीख परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। रेल मंत्रालय की 18 नवंबर की आधिकारिक सूचना के अनुसार, सूरत से बिलिमोरा के बीच 50 किलोमीटर लंबे हिस्से में ओवरहेड विद्युतीकरण प्रणाली को 20 नवंबर को ऊर्जीकृत करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। यह कार्य पूरा होने पर उस हिस्से में विद्युत प्रणाली सक्रिय हो जाएगी। इसके साथ ही आम नागरिकों और निर्माण क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ भी अनिवार्य होंगी।

2027 में पहली बुलेट ट्रेन सेवा का लक्ष्य

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 24 अक्टूबर के आलेख के अनुसार, पहली हाई-स्पीड रेल सेवा 2027 की अंतिम तिमाही में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभिक सेवा सूरत और वापी के बीच शुरू करने की योजना का उल्लेख भी किया गया है। इसके बाद शेष कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से परिचालन के लिए तैयार किया जाएगा। हालांकि, निर्धारित समय पर सेवा शुरू करने के लिए निर्माण के साथ-साथ ट्रेनसेट, ट्रैक, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग और सुरक्षा प्रणालियों का परीक्षण भी आवश्यक होगा। इस परियोजना का महत्व भविष्य की रेल योजनाओं से भी जुड़ा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में लगभग चार हजार किलोमीटर लंबाई वाले सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इनमें दिल्ली-वाराणसी, दिल्ली-लखनऊ, मुंबई-पुणे, चेन्नई-बेंगलुरु, बेंगलुरु-हैदराबाद, चेन्नई-हैदराबाद तथा वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी मार्ग शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 16 लाख करोड़ रुपये के संभावित निवेश का उल्लेख रेल मंत्री ने अपने आलेख में किया है। मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर से प्राप्त अनुभव, निर्माण तकनीक, मानकीकरण और प्रशिक्षित मानव संसाधन इन भावी परियोजनाओं के लिए आधार तैयार कर सकते हैं।

संपादकीय

अश्लीलता की लीला

इसमें दो राय नहीं कि सोशल मीडिया समाज में सहज-सरल संवाद व मुखर अभिव्यक्ति का माध्यम बना है। लेकिन इसमें संपादक नामक संस्था न होने के कारण यह माध्यम धीरे-धीरे अराजक सामग्री, हिंसक अभिव्यक्ति और अश्लीलता का प्रसारक व पोषक बनता जा रहा है। दरअसल, इन कंपनियों का प्रारूप कुछ इस तरह बनाया गया है कि सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करने वाली और बच्चों के मन-मस्तिष्क पर बुरा असर डालने वाली सामग्री दर्शकों का ध्यान ज्यादा खींचती है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया माध्यमों पर बच्चों के यौन-शोषण से जुड़ी सामग्री के विज्ञापनों के प्रसारण को लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया था। बाकायदा मेटा को इस बाबत नोटिस भी दिया गया था। तब भी इन कंपनियों की जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगे थे। विडंबना ही है कि हिंसक, अश्लील व सनसनी फैलाने वाली सामग्री को दर्शकों की ज्यादा प्रतिक्रिया मिलती है, जो इन कंपनियों के अर्थशास्त्र का आधार भी है। विडंबना यह भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का एल्गोरिद्म उपयोगकर्ताओं की अभिरुचि और प्रतिक्रिया के चलते ऐसी सामग्री का अधिक प्रसार करने लगता है। अब सरकार की प्रतिक्रिया व कुछ प्रबुद्ध लोगों के प्रतिरोध के बाद इंस्टाग्राम ने अपने कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम में बदलाव लाने की बात कही है। इसके अंतर्गत दावा किया जा रहा है कि एआई की मदद से अश्लील व हिंसक सामग्री की संस्तुति को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने से पहले ही हटाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी सामग्री को बढ़ावा देने में कंपनी की कोई भूमिका होती है? यदि नहीं, तो इसे कौन बढ़ावा देता है? सवाल यह भी है कि प्लेटफॉर्म पर सामग्री की निगरानी करने वाला एल्गोरिद्म भारतीय परिवेश में वर्जित सामग्री को लेकर अपेक्षित संवेदनशीलता दिखा पाएगा? बहुत संभव है कि सोशल मीडिया पर सूचनाओं व कार्यक्रमों का स्वरूप निर्धारित करने में पश्चिमी समाज का दृष्टिकोण प्रभावी होता हो। तो क्या एआई आधारित निगरानी व्यवस्था समस्या का संपूर्ण समाधान दे पाएगी? वास्तव में इस बात की संभावना कम ही नजर आती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्टरिंग व्यवस्था सोशल मीडिया पर अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री पर पूरी तरह नियंत्रण लगा सकेगी। मशीन मानवीय अहसासों को पूरी तरह नहीं समझ सकती। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मानवीय निगरानी और शिकायतों के शीघ्र निस्तारण का तंत्र भी बने। अब तो जो पश्चिमी देश कल तक सोशल मीडिया का गुणगान करते नहीं अघाते थे, वे भी इससे बच्चों में पनपती विकृतियों की हकीकत समझने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्कॉटलैंड आदि देशों ने एक निर्धारित उम्र के किशोरों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर रोक लगाई है। न्यू मेक्सिको में एक जूरी ने मेटा को इस बात के लिए जवाबदेह ठहराया कि उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वयस्क सामग्री तक बच्चों की पहुंच बनी हुई है, जिससे उनके जीवन में यौन अपराधियों से खतरा बढ़ गया है। लेकिन भारत जैसे देशों में सोशल मीडिया के बच्चों के जीवन पर घातक प्रभावों के बावजूद नियामक कानून न होने से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। मांग की जा रही है कि एक निर्धारित आयु से अधिक उम्र के बच्चे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच बना सकें। विडंबना यह भी है कि बच्चों को संस्कार अब माता-पिता व शिक्षक नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का दोहन करने वाले स्वार्थी तत्व दे रहे हैं, जो भारतीय जीवन-मूल्यों व संस्कारों से मेल नहीं खाते।

विदेश की धरती से भारत की कमियां गिनाने के बजाय राहुल गांधी देश को बताएं समाधान का रास्ता

(लेखक- कांतिलाल मांडोत)

केवल आरोपों से नहीं जीता जाता मतदाताओं का विश्वास कांग्रेस को भी राहुल के बयानों पर आत्ममंथन करना चाहिए

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और सत्ता को जवाबदेह बनाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन विपक्ष की राजनीति केवल आलोचना और आरोपों तक सीमित रह जाए तो जनता के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगते हैं। देश को केवल यह बताने से काम नहीं चलेगा कि समस्याएं कितनी हैं, बल्कि यह भी बताना होगा कि उनका समाधान कैसे होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने भारत में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देश के युवाओं को भविष्य की चिंता सता रही है और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर सवाल हैं। इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी और चुनावी निष्पक्षता लोकतंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की समस्याओं को विदेश में गिनाने से उनका समाधान निकल आएगा? क्या राहुल गांधी के पास इन समस्याओं को दूर करने की कोई ठोस योजना भी है? पिछले ग्यारह वर्षों में राहुल गांधी कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। अलग-अलग अवसरों पर उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, कश्मीर, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर अपनी बात रखी है। लोकतंत्र में किसी भी नेता को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता विदेश में भारत की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाता है तो उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह देश की उपलब्धियों और संभावनाओं को भी सामने रखे। भारत केवल समस्याओं से घिरा देश नहीं है। यहां विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, सड़क, रेल और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। भारतीय युवा दुनिया के अनेक देशों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। इन उपलब्धियों को स्वीकार करना किसी सरकार का समर्थन करना नहीं, बल्कि देश की प्रगति को पहचानना है।

राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस के पास इसका क्या समाधान है। युवाओं को रोजगार चाहिए, केवल भाषण नहीं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कौशल विकास, उद्योगों का विस्तार और छोटे कारोबार को प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता है। सरकार से रोजगार के आंकड़ों और रिक्त पदों पर सवाल पूछना उचित है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी रोजगार नीति जनता के सामने रखनी चाहिए। कांग्रेस यह बताए कि सत्ता में आने पर वह कितने रोजगार के अवसर पैदा करेगी और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाएगी। केवल निराशा का वातावरण बताने से युवाओं का विश्वास नहीं जीता जा सकता।

इसी तरह राहुल गांधी ने मतदाता सूची और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग को हर उचित सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने से पहले उसके समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना भी जरूरी है। यदि कांग्रेस के पास मतदाता सूची में गड़बड़ी या चुनावी अनियमितता से जुड़े दस्तावेज हैं तो उन्हें निर्वाचन आयोग के सामने रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर न्यायालय का रास्ता अपनाना चाहिए। लोकतंत्र में आरोप लगाने की स्वतंत्रता के साथ प्रमाण देने की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। बिना ठोस आधार के बार-बार संदेह जताने से मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हो सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना करना राहुल गांधी के लिए नया नहीं है। राजनीतिक विरोध और वैचारिक मतभेद लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया हैं। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है और उसे उसे जनता के सामने रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन हर मुद्दे को मोदी, शाह या संघ के विरोध से जोड़ देने से जनता की मूल समस्याओं पर चर्चा कमजोर पड़ जाती है। देश की राजनीति व्यक्तियों के विरोध से आगे बढ़कर नीतियों और विकास के विकल्पों पर केंद्रित होनी चाहिए।

यहां एक बड़ा सवाल कांग्रेस नेतृत्व से भी है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता आखिर चुप क्यों रहते हैं? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा मंच नहीं है जहां विदेश में दिए गए बयानों की समीक्षा हो सके? क्या पार्टी नेतृत्व यह नहीं देखता कि इस तरह के बयानों से आम मतदाता के बीच क्या संदेश जाता है? किसी भी राजनीतिक दल में नेतृत्व की बात महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पार्टी की सामूहिक जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। कांग्रेस को अपने नेता के हर बयान का समर्थन करने के बजाय तथ्यों के आधार पर आत्ममंथन करना चाहिए। यदि किसी बयान से देश के भीतर या बाहर गलत संदेश जाता है तो उस पर स्पष्टता देना पार्टी का दायित्व है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने की है। 2014 से पहले भ्रष्टाचार के अनेक आरोप और विवाद तत्कालीन सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन गए थे। जनता ने चुनाव में अपना निर्णय सुनाया और सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके बाद भी कांग्रेस अपने संगठन और राजनीतिक कार्यशैली में अपेक्षित बदलाव नहीं कर पाई। केवल प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने से पार्टी का खोया जनाधार वापस नहीं आने वाला। जनता को यह जानना है कि कांग्रेस के पास देश के विकास, रोजगार, शिक्षा, किसान, मजदूर और मध्यमवर्ग के लिए कौन सी नई योजनाएं हैं। राजनीति में विरोध करना आसान है, लेकिन जनता के सामने भरोसेमंद विकल्प रखना कठिन जिम्मेदारी है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि मतदाता अब केवल भाषण सुनकर निर्णय नहीं करता। वह काम, नेतृत्व, नीतियों और भविष्य की योजनाओं को भी देखता है। विदेश में जाकर भारत की कमियां गिनाने के बजाय उन्हें यह बताना चाहिए कि उन कमियों को दूर करने के लिए उनकी पार्टी क्या करेगी। सरकार को भी आलोचनाओं का जवाब तथ्यों और अपने काम के आधार पर देना चाहिए।

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है। देश की छवि किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। सरकार की गलतियों पर सवाल उठना चाहिए और विपक्ष की गलतियों पर भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि लगातार आरोप लगाने से मतदाताओं का दिल नहीं जीता जा सकता। कांग्रेस को भी अपने नेतृत्व से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर पार्टी देश को कौन सा रास्ता दिखाना चाहती है।

सेवाभाव ही सर्वोपरि



एकनाथ देवगढ़ राज्य के दीवान जनार्दन स्वामी के शिष्य। एक बार गुरू देव ने एकनाथ को राजदरबार का हिसाब करने को कहा। एकनाथ बहि-खाता लेकर हिसाब करने बैठ गये। दूसरे ही दिन सुबह हिसाब राजदरबार में देना था। सारा दिन हिसाब लिखने और करने में बीत गया। दिन में बैठे कब रात हो गयी उन्हें पता ही न चला। सेवक दीपक जलाकर चला गया। हिसाब में एक पायी की भूल आ रही था। आधी रात बीत गयी मगर भूल पकड़ में ही नहीं आ रही थी। संत जी हिसाब में खोये रहे। भोर फटते ही गुरू देव एकनाथ के कमरे में आए तो सेत जी को हिसाब में खोये पाया।

बहियों पर अंधेरा होने पर भी एकनाथ हिसाब में लगे रहे। इतने में एक पायी की भूल पकड़ में आ गयी। एकनाथ खुशी से चिल्ला पड़े,मिल गयी,मिल गयी। गुरू देव ने पूछा,क्या मिल गया बेटा? एकनाथ विस्मय से बोले कि हिसाब में एक पायी की भूल पकड़ में नहीं आ रही थी वह मिल गयी है। लाखों के हिसाब में एक पायी की भूल के लिए रात भर का जागरण।

गुरू देव की सेवा में इतनी लगन और दृढ़ निश्चय देखकर गुरू देव के दिल से गुरूकृपा बह निकली क्योंकि उन्हें ज्ञानामृत की वर्षा करने के लिए योग्य अधिकारी जो मिल गया था।

विचार मंथन

ट्रंप का भारतीय इकोनॉमी की तारीफ के मायने

(लेखक - डॉ. हिदायत अहमद खान)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हैं और भारत की करीब सात प्रतिशत विकास दर को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए उदाहरण बताते हैं, तो इसे केवल भारत के प्रति उनके बदले हुए नजरिये के रूप में देखना उचित नहीं होगा। उनकी इस टिप्पणी के पीछे अमेरिकी घरेलू राजनीति, आर्थिक नीतियों और फेडरल रिजर्व के साथ जारी टकराव की पृष्ठभूमि भी है। सवाल यह है कि जिस भारत पर उनके प्रशासन ने टैरिफ संबंधी दबाव बढ़ाया, जिसके नागरिकों के लिए वीजा नीतियां सख्त की गईं, उसी भारत की आर्थिक व्यवस्था अचानक उन्हें इतनी आकर्षक क्यों दिखाई देने लगी? ट्रंप की इस बात में दम है कि भारत में ब्याज दरें कम हैं और जीडीपी सात प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इसके मुकाबले उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास-दर का जिक्र करते हुए दावा किया कि यदि अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं तो विकास दर 14, 15 या 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उन्होंने अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अच्छे आर्थिक आंकड़े आने के बावजूद केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने की दिशा में काम करता है। ट्रंप का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सरकारी कर्ज चुकाने की क्षमता मजबूत करने के लिए ब्याज दरें कम होनी चाहिए। दरअसल, ट्रंप और फेडरल रिजर्व के बीच ब्याज दरों को लेकर मतभेद नया नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करे, ताकि कारोबार, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन मिले। दूसरी ओर फेडरल रिजर्व का प्रमुख दायित्व महंगाई को नियंत्रित रखना और रोजगार के स्तर को संतुलित बनाए रखना है। यही वजह है कि वह केवल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप ब्याज दरों में बदलाव नहीं कर सकता। मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का उद्देश्य भी यही है कि आर्थिक फैसले राजनीतिक दबाव से प्रभावित न हों।

ट्रंप की टिप्पणी के समय अमेरिका में महंगाई का दबाव भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सितंबर में व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) आधारित महंगाई दर 3.6 प्रतिशत और कोर पीसीई महंगाई दर 3.1 प्रतिशत थी, जबकि फेड का दीर्घकालिक लक्ष्य दो प्रतिशत है। ऐसे में ब्याज दरों में जल्द और बड़ी कटौती महंगाई को फिर बढ़ाने का जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए ट्रंप का यह दावा कि कम ब्याज दरों से अमेरिकी विकास दर सीधे 15 या 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, एक राजनीतिक और आर्थिक अनुमान है, कोई स्थापित आर्थिक निष्कर्ष नहीं। ब्याज दरें विकास को प्रभावित करती हैं, लेकिन उत्पादकता, निवेश, रोजगार, मांग और वैश्विक परिस्थितियां भी इसमें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। भारत की तारीफ को भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में भी समझना होगा। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में टैरिफ को लेकर तनाव पैदा हुआ। अमेरिकी नीतियों का असर भारतीय निर्यातकों और कारोबारियों की योजनाओं पर पड़ा। वीजा नियमों में सख्ती ने भारतीय पेशेवरों और अमेरिका में काम करने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं के सामने भी अनिश्चितता बढ़ाई। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की व्यक्तिगत निकटता और उनकी तारीफ के बयान लगातार चर्चा में रहे हैं। कुछ दिन पहले मोदी को टफ मैन कहना और अब भारतीय अर्थव्यवस्था को उदाहरण बनाना इसी सिलसिले का हिस्सा है। लेकिन कूटनीति में व्यक्तिगत प्रशंसा और नीतिगत सहयोग दो अलग-अलग बातें हैं। नेताओं के बीच मित्रता के सार्वजनिक प्रदर्शन से व्यापारिक बाधाएं अपने आप समाप्त नहीं होतीं। भारत के लिए महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिकी बाजार तक पहुंच, निर्यात पर शुल्क, तकनीकी सहयोग, निवेश और भारतीय पेशेवरों के वीजा जैसे मुद्दों पर ठोस प्रगति हो। इसी तरह अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा बाजार, निवेश का अवसर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देशों के आर्थिक हित एक-दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए आपसी मतभेदों का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहता।

शेयर बाजारों में अनिश्चितता और सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव भी वैश्विक आर्थिक माहौल की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हैं। हालांकि इन बदलावों का कारण केवल भारत-अमेरिका संबंधों को नहीं माना जा सकता। वैश्विक ब्याज दरें, भू-राजनीतिक तनाव, निवेशकों की धारणा और मुद्रा बाजार भी इन पर असर डालते हैं। इसलिए ट्रंप की भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ को उपलब्धि के प्रमाणपत्र से अधिक एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। भारत की सात प्रतिशत विकास दर निश्चित रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी स्थिति को रेखांकित करती है, लेकिन विकास की निरंतरता के लिए घरेलू निवेश, रोजगार, विनिर्माण और निर्यात को मजबूत करना जरूरी है। भारत को अमेरिकी प्रशंसा से अधिक अपने आर्थिक हितों पर ध्यान देना होगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

डीटीसी बढ़ाएगा कमाई, बस डिपो पर बनेंगे पेट्रोल पंप

नई दिल्ली ।

दिल्ली परिवहन विभाग (डीटीसी) अपनी गैर-किराया आय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। विभाग अपने बस डिपो पर पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसीएल) के साथ एक समझौता करने की योजना बना रहा है। यह पहल डीटीसी की यात्रा किराए के अलावा अन्य गतिविधियों से राजस्व बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसमें बसों पर विज्ञापन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत निगम की जमीन का पुनर्विकास भी शामिल है। हाल ही में हुई एक बैठक में इंडियन ऑयल के साथ परियोजना का ब्योरा अंतिम रूप देने और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राजस्व जुटाने के लिए अन्य कंपनियों के साथ भी इसी तरह की परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने पर सहमति बनी। इस कदम से डीटीसी को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

टाटा ट्रस्ट की बैठक में लिस्टिंग पर टली चर्चा, विवादित मुद्दों पर रहस्य बरकरार

26 नवंबर को टाटा संस की बोर्ड बैठक में सूचीबद्धता पर अहम चर्चा की उम्मीद

नई दिल्ली ।

टाटा समूह के भीतर बढ़ते अंदरूनी मतभेदों के बीच सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में टाटा संस की शेयर बाजार में सूचीबद्धता या पुनर्गठन जैसे विवादित मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। करीब दो घंटे चली इस बैठक को नियमित करार देते हुए मुख्य रूप से सामाजिक और परोपकारी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई, जिससे समूह के भविष्य पर अनिश्चितता बनी रही। नोएल टाटा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुणे के जहांगीर अस्पताल के लिए करीब 50 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। न्यासियों ने इसे सामान्य कामकाज से जुड़ी नियमित बैठक बताया। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में लगभग 66 फीसदी हिस्सेदारी है, जो समूह के बड़े फैसलों में ट्रस्ट की भूमिका को अहम बनाती है। अब सबकी निगाहें 26 नवंबर को प्रस्तावित टाटा संस के निदेशक मंडल की अगली बैठक पर हैं, जहां कंपनी की शेयर बाजार में सूचीबद्धता पर चर्चा की संभावना है। 17 सितंबर की पिछली बैठक में लिस्टिंग और अध्यक्ष के तीसरे कार्यकाल पर मतभेद सामने आए थे, जिसका नोएल टाटा ने विरोध किया था। आरबीआई के नियमों से बचने के लिए, सहायक कंपनियों के विलय से पुनर्गठन का विकल्प भी है। रतन टाटा ट्रस्ट के प्रशासनिक मुद्दों ने भी जटिलताओं को बढ़ाया है। समूह के भविष्य पर उद्योग जगत की नजरें बनी हुई हैं।

ईवी चार्जिंग में डिस्कॉम का असहयोग- पीएम सलाहकार

तरुण कपूर ने नोडल अधिकारी, उच्च लागत व कम उपयोग पर जताई चिंता

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के अपर्याप्त सहयोग पर गंभीर चिंता जताई है। सायएम सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत के सरप्लस बिजली उत्पादन के बावजूद, डिस्कॉम ईवी को बिजली खपत के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में नहीं देख रही हैं।

कपूर ने हर डिस्कॉम में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की वकालत की, ताकि चार्जिंग केंद्र संचालकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। कपूर ने डिस्कॉम के गैर-सहयोगी रवैये की आलोचना की, विशेषकर 200 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के ग्रिड कनेक्शन पर मोटी लागत वसूलने के लिए।

उन्होंने कहा कि डिस्कॉम को समझना होगा कि ईवी उनके लिए एक बड़ा राजस्व क्षेत्र बनेगा, न कि केवल उद्योग। सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बिजली कनेक्शन लागत के लिए बजट प्रावधान किए हैं, लेकिन इस आवंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा उपयोग ही नहीं हुआ है, जबकि सरकार आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धन देने को भी तैयार है। उन्होंने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के कम उपयोग (कई स्थानों पर 1 फीसदी से भी कम) पर भी चिंता जताई, जिससे रखरखाव प्रभावित होता है और कई स्टेशन बेकार हो जाते हैं। कपूर ने सुझाया कि चार्जिंग स्टेशन ऐसी जगहों पर हों जहां वाहन आम तौर पर देर तक रुक सकें।

उतार-चढ़ाव के बीच नई ऊंचाइयों पर रहा भारतीय शेयर बाजार

-विदेशी निवेशकों का निरंतर प्रवाह व कच्चे तेल की नरमी से बाजार को मिला समर्थन



मुंबई ।

बीता सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के लिए एक गतिशील और उतार-चढ़ाव भरा रहा, जिसने निवेशकों को कई मोड़ दिए। एक मजबूत शुरुआत के बाद बाजार को बीच सप्ताह में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर शानदार वापसी करते हुए नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। इस दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का निरंतर प्रवाह और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी की उम्मीदों ने बाजार को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। भारतीय रुपया भी शुरुआती कमजोरी के बाद सप्ताह के अंत तक डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, जिससे बाजार की समग्र सकारात्मक धारणा को बल मिला। सप्ताह की शुरुआत सोमवार को जोरदार तेजी के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 450 अंक से अधिक चढ़ा, वहीं निफ्टी ने 25,250 के महत्वपूर्ण स्तर को पार किया। एफपीआई की बढ़ी हुई खरीद और तेल कीमतों में गिरावट की उम्मीदों से बाजार को मजबूती मिली। दिन के अंत में सेंसेक्स 512.34 अंक बढ़कर 82,104.79 पर और निफ्टी 146.80 अंक की वृद्धि के साथ 25,291.10 पर बंद हुआ। एशियन पेंट, एयरटेल, आईटीसी और टाटा कंस जैसे शेयरों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। मंगलवार को भी यह सकारात्मक रुझान जारी रहा, जिससे सेंसेक्स 427.40 अंक चढ़कर 82,532.19 पर और निफ्टी 96.31 अंक बढ़कर 25,387.40 पर पहुंच गया, जो बाजार में मजबूत सकारात्मक धारणा को दर्शाता है। हालांकि, सप्ताह के मध्य में बुधवार को बाजार ने दो दिन की अपनी तेजी को विराम दिया।

सोने में मिलावट का नया रूप रेनियम-इरिडियम, जीजेसी ने चेताया

मुंबई ।



सोने के आभूषणों में रेनियम और इरिडियम जैसी धातुओं की मिलावट से वजन बढ़ाने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। इसी के मद्देनजर, आभूषण उद्योग निकाय जीजेसी (अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद) ने शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को इस मुद्दे पर आगाह करते हुए कारोबारियों और ग्राहकों दोनों से सावधानी बरतने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन धातुओं का इस्तेमाल सोने की शुद्धता बढ़ाए बिना उसका वजन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इससे खरीदारों को आभूषण के वास्तविक वजन और शुद्धता के बारे में गलत जानकारी मिलती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जीजेसी ने बताया कि बीआईएस इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीजेसी ने सभी आभूषण कारोबारियों से विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे गए सोने की गुणवत्ता की कड़ी जांच करने का आग्रह किया है। ग्राहकों को कम बनावट शुल्क के लालच में न आने, विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदारी करने, बीआईएस केयर ऐप से हॉलमार्क की पुष्टि करने और जीएसटी बिल लेने की सलाह दी गई है। किसी भी मिलावट या धोखाधड़ी की स्थिति में जीजेसी या सीधे बीआईएस में शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है।

टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर पर ब्रोकरेज सतर्क, 13 फीसदी गिरावट का अनुमान

कंपनी सॉफ्टवेयर, एयरोस्पेस और इंजीनियरिंग सेवाओं पर केंद्रित, लाभप्रदता बढ़ाने पर भी जोर

मुंबई ।

टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2030 तक अपने कारोबार को 1.1 से 1.3 अरब डॉलर तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी रणनीति प्रस्तुत की है। हाल ही में निवेशक दिवस पर पेश की गई इस योजना में सॉफ्टवेयर, एयरोस्पेस और इंजीनियरिंग सेवाओं को प्रमुख विकास इंजन के रूप में रेखांकित किया गया है। हालांकि, इन बुलंद लक्ष्यों के बावजूद, ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इसके शेयर को बेचने की सलाह दी है, यह मानते हुए कि मौजूदा बाजार मूल्य में भविष्य की अधिकांश वृद्धि पहले ही शामिल हो चुकी है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2027 से 2030 के बीच राजस्व में सालाना 15-20 फीसदी की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। कंपनी केवल कारोबार के आकार पर नहीं, बल्कि मुनाफे में भी सुधार पर केंद्रित है। इसका ऑपरेटिंग मार्जिन वित्त वर्ष 2026 के 15.5 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही तक 17 फीसदी और वित्त वर्ष 2030 तक 20 फीसदी से अधिक करने की योजना है। सॉफ्टवेयर कारोबार कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र है, जो वित्त वर्ष 2021 के 48 लाख डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 6.4 करोड़ डॉलर हो गया है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 में पुराने सॉफ्टवेयर कारोबार से 10 करोड़ डॉलर का राजस्व हासिल करना और अगले तीन वर्षों में इसमें अतिरिक्त 10 करोड़ डॉलर जोड़ना है।



एयरोस्पेस क्षेत्र में भी पिछले पांच वर्षों में लगभग 40 फीसदी की सालाना वृद्धि देखी गई है। टाटा टेक्नोलॉजीज वित्त वर्ष 2028 तक इस कारोबार को 10 करोड़ डॉलर के वार्षिक राजस्व स्तर तक पहुंचाना चाहती है, जिसके बाद वित्त वर्ष 2030 तक इसमें 25-30 फीसदी सालाना वृद्धि का अनुमान है। विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक वाहन उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर की बढ़ती भूमिका, साथ ही एआई का उपयोग, कंपनी के लिए नए अवसर पैदा करेगा और लागत दक्षता बढ़ाएगा।

सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट से निवेशकों में असमंजस

डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेड के सख्त रुख ने कीमती धातुओं को किया कमजोर

मुंबई ।

सोने और चांदी की कीमतों में हालिया भारी गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है। इस गिरावट ने एक ओर जहां गहनों के खरीदारों को राहत पहुंचाई है, वहीं निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है कि क्या यह खरीदारी का सही समय है या कीमतों में और गिरावट का इंतजार किया जाए। पिछले कुछ दिनों से जारी यह तेज कमजोरी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में देखी जा रही है, जिसके पीछे कई वैश्विक आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर 20 नवंबर को दिसंबर अनुबंध वाला सोना गिरकर 1,21,719 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जो कई वर्षों का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है। इस साल जनवरी में 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद से सोने में करीब 33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह, चांदी भी अपने रिकॉर्ड 4.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से फिसलकर लगभग 2.72 लाख रुपये पर पहुंच गई है, जिसमें लगभग 62 प्रतिशत की भारी कमजोरी आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है। कॉमेक्स पर सोना करीब 3520 डॉलर प्रति औंस तक लुढ़का है, जबकि चांदी ने एक सप्ताह में 13 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी है। विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर आक्रामक रुख, डॉलर की लगातार मजबूती और सरकारी बॉन्ड की बढ़ती यील्ड इस गिरावट के प्रमुख कारण हैं। दिसंबर में अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित वृद्धि की अटकलों से निवेशक सोने जैसे गैर-ब्याज देने वाले विकल्पों से दूर हट रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ निवेशकों द्वारा नकदी जुटाने के लिए अन्य संपत्तियों की बिकवाली ने भी कीमतों पर दबाव बढ़ाया है।

ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और युवाओं की आवाजाही पर बनी सहमति

एक लाख युवाओं को आवाजाही, व्यापारिक जांच समाप्त

ब्रसेल्स।

ब्रसेल्स में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) ने ब्रेक्जिट के बाद अपने बिगड़े संबंधों को सुधारने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। दोनों पक्षों ने व्यापार, कार्बन उत्सर्जन और युवाओं की आवाजाही से जुड़े समझौतों पर सहमति जताई, जिसे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने महत्वपूर्ण मोड़ और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने ऐतिहासिक समझौता करार दिया है। इन समझौतों के तहत, 1 लाख युवाओं को तीन साल तक एक-दूसरे के देशों में रहने व काम करने की अनुमति मिलेगी। पौधों व पशु उत्पादों पर व्यापारिक जांच खत्म होगी, जिससे कारोबार आसान होगा। कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था भी जुड़ेगी। प्रधानमंत्री बर्नहम ने ब्रेक्जिट को असफल बताते हुए फायदे से ज्यादा नुकसान की बात स्वीकार की। उन्होंने भविष्य में ईयू के साथ संबंधों के सभी विकल्प खुले रखने की बात कही, जिसमें दोबारा समूह में शामिल होना भी शामिल है, हालांकि इसे लंबी प्रक्रिया बताया। छात्र शुल्क जैसे कुछ मुद्दों पर छह महीने में सहमति बनाने का लक्ष्य है।

सरकारी आईटी खरीद में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता

स्थानीय कलपुर्जों की हिस्सेदारी के नियम सख्त

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब लैपटॉप, डेस्कटॉप और सर्वर सहित छह प्रमुख आईटी हार्डवेयर उत्पादों की सरकारी खरीद में घरेलू कलपुर्जों का योगदान बढ़ाने के लिए निर्धारित प्रतिशत में वृद्धि की गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2017 के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश में संशोधन किया है। यह बदलाव देश में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने, उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। इसका लक्ष्य स्थानीय कलपुर्जों का उपयोग करने वाले उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देना है। संशोधित व्यवस्था के तहत, डेस्कटॉप पीसी, ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) सहित छह आईटी हार्डवेयर उत्पाद शामिल हैं। घरेलू मूल्यवर्धन की गणना अंतिम उत्पाद की कुल लागत में स्थानीय कलपुर्जों की लागत के प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

घरेलू बचत में इक्विटी फंडों की बढ़ती हिस्सेदारी,एयूएम 7.7 गुना बढ़ा



मुंबई ।

भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में पिछले दस वर्षों में निवेशकों का रुझान इक्विटी योजनाओं की ओर तेजी से बढ़ा है। इस अवधि में इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) की परिसंपत्तियां कुल उद्योग की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ी हैं, जो घरेलू बचत में शेयर बाजार की बढ़ती भूमिका को दर्शाती हैं। अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2026 के बीच, इक्विटी और ईएलएसएस फंड का प्रबंधनाधीन निवेश 7.7 गुना बढ़कर 37.18 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग की संपत्ति 5.1 गुना बढ़कर 83.39 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची। इस दौरान इक्विटी योजनाओं की कुल एयूएम में हिस्सेदारी 29.8 फीसदी से बढ़कर 44.6 फीसदी हो गई, जिसमें 14.8 फीसदी अंक की वृद्धि दर्ज की गई।

इक्विटी और ईएलएसएस फंड की चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) 22.6 फीसदी रही, जबकि पूरे उद्योग की 17.7 फीसदी।

हालांकि, इक्विटी फंडों की हिस्सेदारी में हर साल लगातार वृद्धि नहीं हुई; अक्टूबर 2020 में इसमें गिरावट आई, लेकिन बाद में तेजी से सुधार हुआ। इक्विटी श्रेणी में, स्मॉल कैप फंड का एयूएम 9.2 गुना बढ़कर 4.41 लाख करोड़ रुपये हुआ, जबकि सेक्टोरल और थीमैटिक फंड की संपत्ति 8.3 गुना बढ़कर 5.38 लाख करोड़ रुपये हो गई। निवेशकों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2026 तक कुल फोलियो 8.63 करोड़ से बढ़कर 28.78 करोड़ और इक्विटी फोलियो 6.21 करोड़ से बढ़कर 19.22 करोड़ हो गए। यह रुझान घरेलू बचत में शेयर बाजार की बढ़ती भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जानकारों के अनुसार, एयूएम में यह वृद्धि केवल नए निवेश से नहीं, बल्कि बाजार में शेयरों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से भी प्रेरित है।

डीएसपी म्यूचुअल फंड की नई रणनीति, गिरावट में बढ़ाएगा सोना-चांदी में निवेश

कीमतें और गिरने पर चरणबद्ध तरीके से बढ़ाएगा निवेश, चांदी 47 डॉलर और सोना 3850 डॉलर से शुरू

मुंबई ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट के बाद डीएसपी म्यूचुअल फंड ने कीमती धातुओं में निवेश बढ़ाने की नई रणनीति तैयार की है। डीएसपी मल्टी एसेट ओम्नी फंड ऑफ फंड्स कीमतें और नीचे आने पर चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करेगा, जिसका उद्देश्य लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर पैदा करना है। इस रणनीति के तहत, चांदी में 47 डॉलर प्रति औंस से नीचे आने पर शुरुआती खरीदारी (0.5 फीसदी पोर्टफोलियो) शुरू की गई है। योजना के मुताबिक, चांदी की कीमत में हर दो डॉलर की गिरावट पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत और 42 डॉलर प्रति औंस से नीचे आने पर एक प्रतिशत निवेश बढ़ाया जाएगा। यदि कीमत 37 डॉलर तक गिरती है, तो कुल अतिरिक्त निवेश पांच प्रतिशत तक पहुंच सकता है। सोने में भी ऐसी ही रणनीति अपनाई जा रही है, जहां करीब 3850 डॉलर प्रति औंस पर शुरुआती 0.5 प्रतिशत निवेश किया गया है। इसके बाद, सोने की कीमत में हर 100 डॉलर की गिरावट पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत निवेश की योजना है, जिसमें 3800, 3700 और 3600 डॉलर जैसे स्तर शामिल हैं। यह फंड को अपने बेंचमार्क (सोना 15 फीसदी, चांदी 5 फीसदी) के मुकाबले कम निवेश के अंतर को पाटने में मदद करेगा। फंड निवेश के फैसले के लिए कई संकेतकों का विश्लेषण कर रहा है, जिसके अनुसार फिलहाल सोना अपनी अनुमानित उचित कीमत से 15 प्रतिशत और चांदी 28 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रही है। अतिरिक्त खरीदारी के लिए मुख्य रूप से डेट निवेश घटाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर शेयर बाजार के कुछ क्षेत्रों में आवंटन भी बदला जाएगा। हालांकि, कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है और यह रणनीति निश्चित मुनाफे की गारंटी नहीं देती।

भारत में एआई क्रांति, 90 फीसदी कंपनियां बढ़ा रहीं तकनीकी कार्यबल

रिपोर्ट के अनुसार, भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर

मुंबई ।

देश में कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित सेवाओं और राजस्व के नए स्रोत पैदा करने के लिए भारतीय नियोक्ता अपनी प्रौद्योगिकी कार्यबल क्षमता बढ़ा रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90 प्रतिशत कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं, यह वैश्विक स्तर पर अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा अनुपात है। एक वैश्विक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का यह आंकड़ा अमेरिका (93 फीसदी) के बाद दूसरे नंबर पर है और 86 फीसदी के वैश्विक औसत से काफी ऊपर है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एआई का कौशल रखने वाले डेवलपर को शुरुआती स्तर पर पारंपरिक डेवलपर की तुलना में दोगुने से अधिक वेतन मिल सकता है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह बढ़त 79 फीसदी तक है। हालांकि, 50 फीसदी भारतीय नियोक्ताओं को बेहतर वेतन देने वाली प्रतिस्पर्धी कंपनियों के हाथों अक्सर शीर्ष प्रतिभाओं को गंवाना पड़ता है, फिर भी 53 फीसदी कंपनियां प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छंटनी के कारण नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को सफलतापूर्वक काम पर रख पाई हैं। रैंडस्टैड इंडिया के प्रबंध निदेशक नारायण अय्यर ने कहा कि एआई, प्रौद्योगिकी प्रतिभा परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल रहा है और उभरते कौशल की मांग उनकी उपलब्धता से लगातार अधिक बनी हुई है।

तुम्हें कितने मार्क्स मिले...?

पेपर का रिजल्ट आने पर अपने बच्चे से कभी न पूछें ये सवाल



यह बात सच्ची है कि जब आप अपने बच्चे से अक्सर 'तुम्हें कितने मार्क्स मिले?' ये सवाल पूछते हैं, तो यह कई तरह से उनकी सेल्फ़-वर्थ, सिखने की प्रक्रिया और मनोधर्म पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आज हम आपको बताते हैं कि ये सवाल बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

क्यों यह सवाल नुकसान पहुंचाता है

जब सबसे पहला सवाल ये होता है कि 'कितने अंक आए?', तो बच्चे को यह संदेश जाता है कि अंक = मूल्य = आपकी योग्यता। पर वास्तव में 'अंक' सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम हैं, व्यक्ति की सम्पूर्ण क्षमता या गुण नहीं। उदाहरण के लिए, एक लेख कहता है कि यह हो सकता है कि बच्चों को यह महसूस हो जाए कि उनका पूरा मूल्य सिर्फ उनकी ग्रेड्स से तय होता है। जब यह सवाल बार-बार पूछा जाए, तो बच्चे में यह डर बन सकता है कि अगर अंक कम आए तो उन्हें मम्मा-पापा की नाराज़गी या शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। यह दबाव उनकी पढ़ाई, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

सिखने की प्रक्रिया पर ध्यान कम देना

दिए गए मार्क्स के पीछे क्या हुआ- जैसे तैयारी कैसे हुई, कौन-सी चीज कठिन लगी, किस तरीके से समझा जा सकता था, इन पर कम ध्यान जाता है। परिणाम पर ज्यादा फोकस होने से बच्चों में 'स्कोर करने की रणनीति' बन सकती है बजाय 'समझने की रणनीति' के। यदि संवाद का मुख्य आधार सवाल 'कितने अंक?' हो जाए, तो बच्चे हो सकता है कि उस बातचीत को अपेक्षा-पूर्ति के रूप में देखें- न कि खुली बातचीत के रूप में। इससे पिता-माता-बच्चा के बीच भरोसा कम हो सकता है।

बेहतर तरीका — क्या-क्या पूछा जा सकता है

- 'तुम्हारी एक्साम के दौरान सबसे कठिन क्या लगा? उस पर काम कैसे कर सकते हैं?'
- 'क्या तुमको लगता है तुमने उस विषय में यह तरीके आजमाए? अगर नहीं, तो अगली बार कैसे करोगे?'
- 'क्या वो हिस्सा था जिसमें तुमने अच्छा किया? उस पर हम कैसे और सुधार कर सकते हैं?'
- 'पढ़ाई के अलावा तुम्हें क्या-क्या मज़ेदार लगा आज स्कूल में?'

ऐसे सवाल बच्चों की सोचना, भावनाओं को समझने और संवाद बढ़ाने में मदद करते हैं।

सिर्फ कुछ मिनटों में बनाएं ये पांच टेस्टी सैंडविच, बनाने का तरीका भी है बेहद आसान

शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा, जिसे सैंडविच खाना पसंद न हो। तो अगर आपको सैंडविच खाना पसंद है, तो ये खबर आपके लिए खास होने वाली है। चाहे आप ऑफिस जा रहे हों, बच्चों के टिफिन की तैयारी कर रहे हों या घर पर कुछ हल्का और टेस्टी खाना चाहते हों—सैंडविच हर मौके के लिए परफेक्ट ऑप्शन माना जाता है।

ऐसे में आज हम आपको पांच तरह के स्वादिष्ट सैंडविच की रेसिपी बताने जा रहे हैं जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में घर पर बना सकते हैं। ये न सिर्फ खाने में लाजवाब हैं बल्कि हेल्दी और एनर्जेटिक भी हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हें बनाने का आसान तरीका और खास टिप्स जिससे आपके सैंडविच बनें बिल्कुल कैफे स्टाइल!

1. वेज ग्रिल सैंडविच

ये सैंडविच बनाना काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो ब्रेड पर बटर लगाएं, उसमें टमाटर, खीरा, आलू, और चटनी लगाएं। अब इसे सैंडविच मेकर में गोल्डन ब्राउन होने तक ग्रिल करें। इसे चटनी और कैचअप के साथ परोसें।

2. पनीर टिक्का सैंडविच

पनीर टिक्का सैंडविच खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को मसालों और दही में मेरिनेट करें। इसके बाद इसे इसे ब्रेड के बीच में रखकर ग्रिल करें और पुदीना चटनी के साथ परोसें।

3. एग मेयो सैंडविच

अगर आपको अंडे खाना पसंद है तो आप उबले अंडे को कद्दूकस करके उसमें मेयोनेज को मिक्स करें। दोनों चीजों को मिक्स करें और फिर नमक, काली मिर्च डालें और टोस्टेड ब्रेड पर लगाएं। बस इसे फिर ग्रिल कर लें और कैचअप के साथ परोसें।

4. चीज कॉर्न सैंडविच

ये सैंडविच ज्यादातर हर किसी को पसंद आता है। ये सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले स्वीट कॉर्न को उबाल लें। अब इसमें चीज और थोड़ा ओरिगेनो मिलाएं। अब इसे इसे ब्रेड में भरकर ग्रिल करें। ये सिंपल सा सैंडविच बच्चों से लेकर बड़े भी खूब चाव से खाते हैं।

5. स्पाइसी चटनी सैंडविच

जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये सैंडविच कमाल का है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड पर हरी चटनी फैलाएं। इस हरी चटनी को तीखा ही रखें। अब चटनी फैलाने के बाद टमाटर और प्याज रखें। आखिर में इसे हल्का टोस्ट करें और गर्मागर्म सर्व करें।



बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चे की बेहतर तैयारी के लिए अभिभावक करें ये काम

जो बच्चे इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए अभिभावकों को भी कुछ तरीके अपनाने चाहिए, ताकि बच्चा बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम ला सके।



10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चे के लिए बोर्ड परीक्षा एक अहम पड़ाव होता है, जो उनके भविष्य को तय करने में मदद करता है। अच्छे अंक आने पर बेहतर कॉलेज में प्रवेश, छात्रवृत्ति और करियर के लिए क्षेत्र तय करने में मदद मिलती है। ऐसे में भारत के अधिकतर सभी स्कूलों,कोचिंग क्लासेज बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करते हैं।

माता-पिता अपने बच्चे की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे अधिक चिंतित होते हैं। ऐसे में वह बच्चे पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन इसका असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है और अतिरिक्त दबाव उन्हें परेशान कर सकता है। बोर्ड परीक्षा बच्चों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होती है और इसमें अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में जो बच्चे इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए अभिभावकों को भी कुछ तरीके अपनाने चाहिए, ताकि बच्चा बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम ला सके।

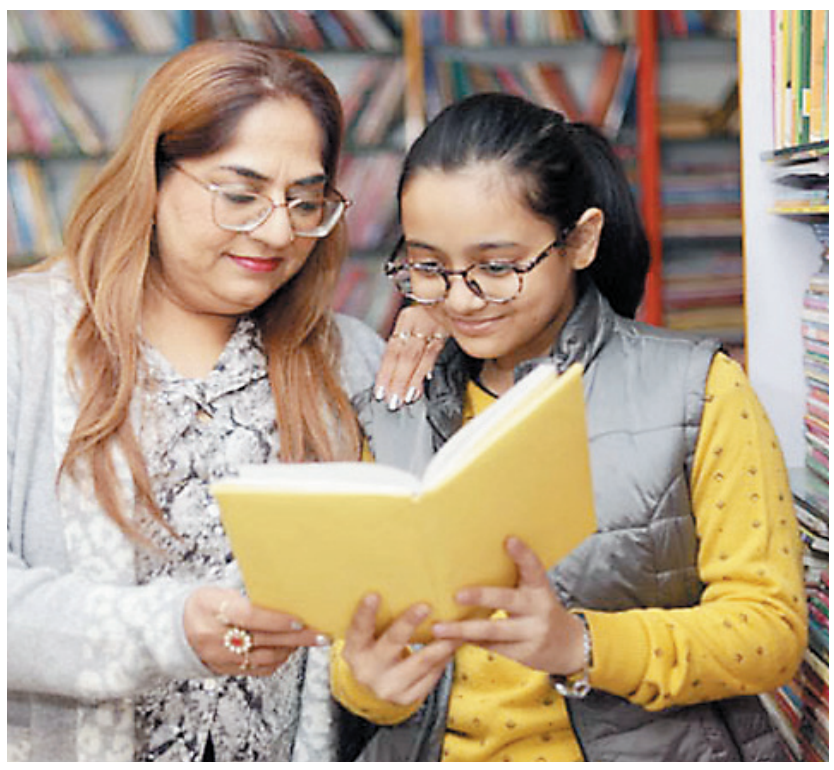

प्रोत्साहित करें

बच्चा दबाव में तब आता है, जब माता पिता अपनी चिंता अत्यधिक जाहिर करते हैं, वो भी नकारात्मक तरीके से। उन पर दबाव बनाने के बजाए माता पिता को बच्चे को परीक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही बच्चे के छोटे-छोटे प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करें।परीक्षा को जीवन-मरण का प्रश्न बनाने की बजाय इसे एक सीखने का अवसर मानें।

पढ़ाई की योजना बनाने में मदद करें

बच्चे के साथ मिलकर एक प्रभावी टाइम टेबल तैयार करें। टाइमटेबल ऐसा हो ताकि पढ़ाई और आराम के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। कठिन विषयों को अधिक समय दें और पिछले साल के प्रश्न पत्र और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान करें।

मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें

इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा मानसिक रूप से परेशान न हो। उसका उत्साहवर्धन करने का प्रयास करें। ऐसी बातें करें जो उसे उत्साहित करें ना कि निराश करें। जैसे 'तुम यह कर सकते हो' और 'मैं तुम्हारे साथ हूं' आदि बातें कहें। बच्चे की तुलना अन्य बच्चों से न करें।

परिणाम को लेकर ज्यादा चिंता न करें

बच्चे को यह समझाएं कि मेहनत का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। परीक्षा के बाद भी उसे यह भरोसा दिलाएं कि आपका प्यार और समर्थन उसके साथ है। परिक्षा में बेहतर अंक को भविष्य के लिए एकमात्र रास्ता न बनाएं।

नियमित ब्रेक और नींद का ध्यान रखें

दिनभर पढ़न से बच्चा होनहार नहीं हो जाएगा। जरूरी है कि हर एक दो घंटे की पढ़ाई के बाद उसे 10-15 मिनट का ब्रेक मिले। इस ब्रेक में वह दिमाग को फ्रेश करें। शारीरिक गतिविधि करे ताकि उसके दिमाग को आराम और सेहत दुरुस्त रह सके। इसके साथ ही नींद बेहतर जरूरी है। बच्चे को कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

खानपान का ध्यान रखें

बच्चे को पौष्टिक भोजन दें, जिसमें फल, सब्जियां, नट्स, और प्रोटीन शामिल हो। जंक फूड देने से बचें। ये सेहत के लिए तो नुकसानदायक होता ही है, एकाग्रता भी भंग करता है। परीक्षा से ध्यान भटकाने वाले कारकों को कम करें, जैसे बच्चे के मोबाइल और सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करें। घर का माहौल ऐसा हो जहां वह पढ़ाई के लिए ध्यान केंद्रित कर सके और शांत वातावरण में मन लगा कर पढ़ सके।

रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान दें

परीक्षा के करीब आते-आते बच्चे को पूरे सिलेबस का रिवीजन करने के लिए प्रेरित करें। समय सीमा के साथ मॉक टेस्ट दें ताकि बच्चे को परीक्षा का अनुभव हो सके।

आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें

बच्चे को समस्याओं को खुद हल करने की आदत डालें। जब बच्चा किसी प्रश्न में अटका हो, तब उसे मार्गदर्शन दें, लेकिन उसे पूरी तरह आप पर निर्भर न बनाएं।

बच्चों में जोड़ों के दर्द के 7 संकेत, आज नजरअंदाज किया तो उम्र भर रहेंगे परेशान

बच्चों में जोड़ों से जुड़ी दिक्कतें केवल उम्रदराज लोगों में नहीं, बल्कि छोटे बच्चों में भी हो सकती हैं। कई बार माता-पिता इसे सामान्य बढ़ने का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि ये दर्द बार-बार हों या रात में बढ़ जाएं, तो ये



जोड़ों की समस्या का संकेत हो सकता है। यहां बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा बताए गए 7 प्रमुख संकेत दिए गए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

रात में बढ़ने वाला दर्द

अगर बच्चे को दिन में ठीक रहता है लेकिन रात को दर्द बढ़ जाता है, तो यह सामान्य नहीं है। ऐसा दर्द सूजन या जोड़ों में सूक्ष्म संक्रमण का संकेत हो सकता है।

चलने या दौड़ने में कठिनाई

यदि बच्चा अचानक लंगड़ाने लगे, धीरे चले या दौड़ने से बचे, तो ये संकेत हैं कि उसके जोड़ों में दर्द या जकड़न (ह्यह्लद्बद्धद्धट्ठद्गह्यह्य) हो सकती है।

सूजन या लालिमा

किसी एक या अधिक जोड़ों में सूजन, लालपन या गर्माहट महसूस होना सूजन (द्बट्ठद्धद्यड्डद्बद्बड्डह्लद्बश्ठ्ठ) का संकेत है। यह आर्थराइटिस या संक्रमण से भी हो सकता है।

सुबह उठते ही जकड़न

यदि बच्चा सुबह उठते ही अपने हाथ-पैरों को मोड़ने या सीधा करने में परेशानी बताता है, तो यह जोड़ों में सूजन या आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है।

किसी विशेष जोड़ में बार-बार दर्द

अगर दर्द हर बार एक ही घुटने, टखने या कोहनी में हो रहा है, तो यह केवल थकान नहीं, बल्कि जोड़ों की कोई आंतरिक समस्या हो सकती है।

बुखार या थकान के साथ दर्द

अगर जोड़ों का दर्द बुखार, कमजोरी या भूख न लगने के साथ हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह संक्रमण या ऑटोइम्यून बीमारी का संकेत हो सकता है।

बच्चे का खेलने से बचना

यदि बच्चा पहले की तरह खेलना, कूदना या चढ़ना-उतरना छोड़ दे, तो यह दर्द से बचने की कोशिश हो सकती है।

कब डॉक्टर को दिखाए

अगर बच्चे का दर्द 2 हफ्तों से ज़्यादा बना रहे, जोड़ों में सूजन या बुखार आ जाए या फिर बच्चा लंगड़ाने लगे या चलने से बचे तो डॉक्टर को जरूर दिखाए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों के जोड़ों के दर्द को 'द्दह्मश्2द्बट्ठद्द श्चड्डद्बट्ठ' मानकर टालना ठीक नहीं। जल्दी जांच कराने पर समस्या का इलाज सरल और प्रभावी हो सकता है। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और हल्की फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के जोड़ों को मजबूत रखते हैं।

शुरू हो गई हैं सर्दियां, बनाकर तैयार करें ये पांच तरह के लड्डू ताकि न हो तबियत खराब



सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को अतिरिक्त पोषण और गर्माहट की जरूरत होती है। इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी अक्सर कमजोर पड़ जाती है, जिससे सर्दी-जुकाम जल्दी हो सकती है। ऐसे में घर पर बने देसी लड्डू न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। पारंपरिक तरीके से बनाए गए लड्डू शरीर को एनर्जी, गर्मी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं।

सर्दी के मौसम में कुछ खास तरह के लड्डू पाचन को बेहतर बनाते हैं, जोड़ों के दर्द से राहत देते हैं और शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। अगर आप ठंड में स्वस्थ और एक्टिव रहना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में इन देसी लड्डुओं को जरूर शामिल करें। आइए जानते हैं ऐसे पांच तरह के लड्डू जो सर्दियों में आपकी तबीयत खराब होने से बचा सकते हैं।

तिल-गुड़ के लड्डू

तिल और गुड़ का मेल सर्दियों में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये शरीर को गर्म रखता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है। इसमें कैल्शियम और आयरन भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है।

गोंद के लड्डू

गोंद से बने लड्डू जोड़ों के दर्द और ठंड से होने वाली कमजोरी में फायदेमंद होते हैं। इसमें घी, मेवा और गेहूं का आटा मिलाकर बनाया जाता है जो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है।

मेथी के लड्डू

मेथी के लड्डू सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। महिलाओं के लिए ये खासतौर पर फायदेमंद माने जाते हैं क्योंकि ये हॉर्मोनल बैलेंस को भी सपोर्ट करते हैं।

मूंगफली के लड्डू

मूंगफली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसके लड्डू ठंड के मौसम में ऊर्जा प्रदान करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। गुड़ के साथ मिलाकर खाने से ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों बन जाते हैं।

सूखे मेवे के लड्डू

बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और खजूर से बने लड्डू विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ये शरीर को ताकत देते हैं और स्किन ग्लोइंग बनाए रखते हैं। तो आप चाहें तो इसे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं।



Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

फिलीपींस में टला बड़ा विमान हादसा, सुरक्षित लैंडिंग से बचे 146 लोग

मनीला ,एजेंसी। फिलीपींस में एयर न्यूगिनी के विमान ने दक्षिणी फिलीपींस के दावाओ शहर में आपातकालीन लैंडिंग की, जिससे एक बड़ा विमान हादसा टल गया। हांगकांग से पापुआ न्यू गिनी जा रहे इस विमान के इंजन में चिंगारी दिखने के बाद यह सुरक्षित लैंडिंग की गई, जिसमें सवार सभी 146 यात्री और चालक दल के सदस्य बाल-बाल बच गए। फिलीपींस की सिविल एविएशन अथॉरिटी (सीएएपी) ने बताया कि यह बोइंग 767-383 ईआर विमान था। इसमें 137 यात्री और 9 चालक दल के सदस्य सवार थे, कुल 146 लोग सवार थे। पायलटों ने दाहिने इंजन में संभावित चिंगारी या आग का संकेत मिलने के बाद तुरंत सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन कर दावाओ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग का अनुरोध किया। विमान अपने तय मार्ग से भटक गया था। लैंडिंग के बाद, सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को इमरजेंसी स्लाइड के ज़रिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलीपींस की सिविल एविएशन अथॉरिटी के प्रवक्ता एरिक अपोलोनियो ने पुष्टि की कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी हताहत नहीं हुआ। यात्रियों को तुरंत हवाई अड्डे के टर्मिनल ले जाया गया और उनके लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई। इमरजेंसी लैंडिंग के कारण दावाओ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से अन्य उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे दो घरेलू उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। हालांकि, सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद मुख्य रनवे को फिर से खोल दिया गया। फिलीपींस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि विमान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और इस घटना के विस्तृत कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

सांसद ने सदन में किया शादी के लिए प्रपोज़, तालियों से गूंजने लगी संसद

सिडनी,एजेंसी। संसद की कार्यवाही आमतौर पर गंभीर बहसों और नीतियों के लिए जानी जाती है, लेकिन 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स संसद में एक ऐसा अनोखा और फिल्मी नजारा देखने को मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया। सिडनी के राइड इलाके से सांसद जॉर्डन लेन ने अपनी विदाई स्पीच के दौरान अपनी 10 साल पुरानी पार्टनर नताली हिसी को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना ने न सिर्फ सदन का माहौल बदल दिया, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। जॉर्डन लेन अपनी विदाई स्पीच यानी वैलेडिक्टरी एड्रेस दे रहे थे, जब उन्होंने अचानक पब्लिक गैलरी में बैठी अपनी पार्टनर नताली हिसी के सामने सगाई की अंगूठी निकाली और सबको चौंकाते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस अचानक आए मोड़ ने न सिर्फ साथी सांसदों को हैरान कर दिया, बल्कि स्पीकर और पब्लिक गैलरी में बैठे लोग भी एक पल के लिए ठगे से रह गए। जॉर्डन लेन ने अपने भाषण के दौरान नताली के साथ अपने 10 साल से ज्यादा पुराने रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका यह रिश्ता कई मुश्किलों और हालात के बीच परवान चढ़ा है और दस साल पहले दोनों का साथ आना एक तरह से संयोग था। उन्होंने नताली की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनके जीवन में हर अच्छी और सच्ची चीज की वजह हैं, और शब्दों में यह बयां कर पाना मुश्किल है कि नताली ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है। अपने भाषण के आखिर में, उन्होंने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि राइड के सदस्य के तौर पर उनका आखिरी सवाल उनके प्यार नताली के लिए है। इतना कहते ही उन्होंने सगाई की अंगूठी निकाली और सीधा शादी का प्रस्ताव रख दिया। जैसे ही जॉर्डन लेन ने यह सवाल पूछा, सदन का गंभीर माहौल पूरी तरह बदल गया और तालियों की आवाज से गूंज उठा। इसके बाद लेन नताली के पास पहुंचे और उनकी उंगली में अंगूठी पहनाई। नताली के हां कहने को लेकर कोई भ्रम न रहे, इसके लिए सांसद ने सदन को मजाकिया अंदाज में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड यानी हैंसार्ड में यह दर्ज कराना चाहते हैं कि नताली ने हां कह दिया है।

थाईलैंड ने अमेरिका से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर शुल्क खत्म करने किया समझौता

ट्रंप बोले-हर साल अमेरिका से 2.6 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद खरीदने की इच्छा भी जताई



वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि थाईलैंड ने अमेरिका से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर शुल्क खत्म करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उनके मुताबिक बैंकॉक ने हर साल अमेरिका से 2.6 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद खरीदने की इच्छा भी जताई है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस खरीद का आंकड़ा और बढ़ाने की कोशिश करेगा। एशिया की चार दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि थाईलैंड ने अमेरिकी उत्पादों पर सभी शुल्क खत्म करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि थाईलैंड ने गैर-शुल्क बाधाओं को भी हटा दिया है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये बाधाएं कौन-सी थीं और शुल्क में कटौती कब से लागू होगी।
मीडिया रिपोर्ट में ट्रंप के मुताबिक 2.6 अरब डॉलर का आंकड़ा थाईलैंड की ओर से हर साल अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने की शुरुआती इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआती आंकड़ा है। हम इससे ज्यादा की मांग करेंगे। थाईलैंड के साथ हुआ समझौता उन दो व्यापारिक समझौतों में शामिल है, जिनकी घोषणा ट्रंप ने अपनी एशिया यात्रा के दौरान की थी। दूसरा समझौता फिलीपींस के साथ एक रूपरेखा के तौर पर हुआ है। ट्रंप ने दोनों समझौतों को अमेरिकी किसानों के लिए फायदेमंद बताया, हालांकि दोनों देशों से की गई उनकी मांगों में अंतर था।
ट्रंप ने बताया कि मनीला में उन्होंने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से एक जनवरी से देश की कृषि संबंधी सभी आयात जरूरतों को अमेरिकी किसानों से पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फिलीपींस अब तक ब्राजील से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद खरीदता रहा है। ट्रंप ने चीन के साथ संभावित टकराव का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में फिलीपींस को अमेरिकी मदद की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि फिलीपींस और मलेशिया अमेरिकी तकनीक तथा सेवाओं का इस्तेमाल अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि आसियान शिखर सम्मेलनों में अमेरिका की भागीदारी का सीधा आर्थिक महत्व है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकी उत्पादों के लिए बड़े बाजार हैं और यहां होने वाली बिक्री से अमेरिका में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने संघर्ष में उनके हस्तक्षेप के लिए आभार जताया और बताया कि उनकी भूमिका के संबंध में नोबेल समिति को पत्र लिखा है।

रियाद पर दागी गईं मिसाइलें, हूती ने जवाबी कार्रवाई का किया दावा

रियाद,एजेंसी। यमन के हूती लड़ाकू समूह ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, इस उन्होंने सऊदी गठबंधन के विशेष अभियान का जवाब बताया। इस हमले के बाद रियाद में दो धमाके सुने गए, जिसके जवाब में सऊदी वायु रक्षा प्रणाली ने राजधानी की ओर दागी गई तीन बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर नष्ट किया। सऊदी ने इससे पहले अपने नागरिकों को संभावित हवाई हमले के प्रति सचेत रहने की सलाह दी थी। हूती समूह ने दावा किया है कि उसने रियाद सहित पूरे सऊदी अरब में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। यह हमला गठबंधन द्वारा शुक्रवार को लाल सागर के बंदरगाह शहर होदेइदा और अन्य स्थानों पर किए गए हमलों के बाद हूती की जवाबी कार्रवाई की धमकी के अनुरूप था। हूती ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर होदेइदा पर हमला होता है, तब वह सऊदी शहर जेद्दा और लाल सागर के अन्य बंदरगाहों को निशाना बनाएगा। समूह ने एयरलाइंस को सऊदी हवाई क्षेत्र को असुरक्षित बताकर वहां उड़ान न भरने की सलाह भी दी थी, हालांकि मक्का और मदीना के पवित्र हवाई क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया। उन्होंने रियाद के वित्तीय जिले और अल-शुकाइक स्थित एक पावर स्टेशन को भी निशाना बनाने की धमकी दी थी। गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मल्की ने बताया कि उनके बलों ने होदेइदा बंदरगाह पर उन परिचालन क्षमताओं को निशाना बनाया, जिनका इस्तेमाल हथियारों की तस्करी और बैलिस्टिक मिसाइलों की ढुलाई के लिए किया जा रहा था। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि यमन की सीमा के पास जिजान क्षेत्र के ऊपर दो और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका गया, जिनका मलबा अल-शुकाइक में गिरा। हमलों के बाद दोनों पक्षों ने अलग-अलग दावे किए हैं। हूती का दावा है कि पिछले 24 घंटों में गठबंधन के हमलों में 41 लोग मारे गए हैं। वहीं, सऊदी समर्थित सशस्त्र बलों का कहना है कि दर्जनों हवाई हमलों और बमबारी में 193 हूती लड़ाके मारे गए या घायल हुए हैं। हूती ने अल-शुकाइक पावर स्टेशन और जिजान बंदरगाह पर सटीक और सीधे हमले कर भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया है। यह नवीनतम घटना महीनों से जारी संघर्ष में हिंसा की बढ़ती गति को दर्शाती है।

अमेरिकी नागरिकों पर साइबर हमले, एफबीआई प्रमुख ने दी कड़ी चेतावनी

वाशिंगटन,एजेंसी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इवेंस्टिगेशन (एफबीआई) के निदेशक काश पटेल ने अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसतरह के अपराधियों को कानून का सामना करना पड़ेगा। एफबीआई प्रमुख पटेल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एफबीआई साइबर खतरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रही है और इसतरह के हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी पोस्ट में एफबीआई प्रमुख पटेल ने ऑपरेशन विंटर शील्ड का जिक्र किया। इस अभियान का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर अमेरिका की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और व्यवसायों, सरकारी प्रणालियों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है। एफबीआई प्रमुख पटेल ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में एफबीआई दुनिया भर के साइबर अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और हम साइबर खतरों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे हैं। हमारा संदेश साफ है- अगर आप अमेरिकी लोगों को निशाना बनाते हैं, तब न्याय आप तक जरूर पहुंचेगा। यह चेतावनी तब आई है जब अमेरिका में साइबर सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हाल ही में, जेपी मॉर्गन चेस से जुड़े थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ, जिससे लगभग 16,000 ग्राहकों की निजी जानकारी लीक होने की आशंका है। बैंक ने गुरुवार को बताया कि उनकी जांच से पता चला है कि हमलावरों ने बाहरी वेंडर्स के पास मौजूद मार्केटिंग डेटा तक पहुंच बना ली थी, जिसमें ग्राहकों के नाम और ईमेल पते शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट अनुसार, एनओएन नामक एक रैनसमवेयर ग्रुप ने डेटा लीक की जिम्मेदारी ली है। खबरों के मुताबिक, इस घटना से वीजा और मास्टरकार्ड से जुड़े व्यावसायिक साझेदार भी प्रभावित हुए हैं, जिनकी ईमेल पते, फोन नंबर और खाता आईडी जैसी संवेदनशील जानकारी लीक हुई है। जेपी मॉर्गन चेस ने आश्वस्त किया है कि उनकी मुख्य सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है और वे प्रभावित ग्राहकों से सीधे संपर्क करके उन्हें मुफ्त क्रेडिट मॉनिटरिंग सहित आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

2070 तक अमेरिका में हिंदुओं की आबादी बढ़कर दोगुनी से भी ज्यादा होगी

रिपोर्ट में खुलासा, अगले पांच दशकों में दुनिया में धार्मिक आबादी की तस्वीर बदलेगी

वाशिंगटन, एजेंसी। दुनिया में धार्मिक विविधता बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले पांच दशकों में दुनिया में धार्मिक आबादी की तस्वीर तेजी से बदलने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2070 तक अमेरिका में हिंदुओं की आबादी बढ़कर दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है, जो एक बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव होगा। रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो, साल 2020 तक अमेरिका में हिंदुओं की आबादी करीब 30 लाख थी, जो देश की कुल जनसंख्या का करीब 0.9फीसदी हिस्सा थी, लेकिन भविष्य के अनुमान बेहद दिलचस्प हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक साल 2070 तक अमेरिका में हिंदुओं की संख्या 74 लाख से 90 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। इस बढ़ोतरी के साथ, अमेरिका में हिंदुओं की कुल आबादी 2फीसदी का आंकड़ा छू लेगी। यह वृद्धि मुख्य रूप से इमिग्रेशन के कारण होने का अनुमान है। भारत और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में हिंदू अमेरिका का रुख कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अवसरों की तलाश में हैं। जानकारों के मुताबिक यही प्रवासन अमेरिका में अगले 50 सालों में धार्मिक विविधता को नया आकार देगा। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में भी हिंदू जनसंख्या में फेरबदल देखने को मिलेगा। वैश्विक स्तर पर, हिंदू आबादी में होने वाली कुल वृद्धि का करीब 88फीसदी हिस्सा अकेले भारत में केंद्रित रहेगा। अनुमान है कि भारत में हिंदुओं की संख्या 2020 के 1.11 अरब से बढ़कर 2070 तक 1.29 अरब के पार जा सकती है। भारत और नेपाल दुनिया के ऐसे दो राष्ट्र बने रहेंगे जहां हिंदू समुदाय स्पष्ट बहुमत में होगा। हालांकि, जनसंख्या वृद्धि की अलग-अलग दरों के कारण भारत की कुल आबादी में हिंदुओं का अनुपात 79फीसदी से घटकर 76फीसदी के आसपास रह सकता है।
आने वाले पांच दशकों में, अमेरिका वैश्विक मानचित्र पर पांचवीं सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाले देश के रूप में उभर सकता है। इस बदलाव से अमेरिका के अंदर धार्मिक समीकरणों पर भी असर पड़ेगा। वहां ईसाई और मुस्लिम समुदाय पहले और दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समूह बने रहेंगे, जबकि हिंदू आबादी यहूदी समुदाय को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक वर्ग बन सकती है। जानकारों के मुताबिक यह स्थिति अमेरिकी समाज में बढ़ते बहुसांस्कृतिक ताने-बाने को दर्शाती है और इस समुदाय की भूमिका वहां की अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण में भी गहरी होगी, क्योंकि शिक्षा और आय के मामले में यह वर्ग पहले से ही अमेरिका के सबसे समृद्ध समुदायों में गिना जाता है।

निखिल गुप्ता ने अपनी गलतियों के लिए अदालत में मांगी माफी , पन्नू हत्या की साजिश मामले में मिली 19 साल 7 महीने की सजा

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में भूमिका के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 19 साल 7 महीने जेल की सजा सुनाई है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला जज विक्टर मारेरो ने शुक्रवार को करीब 80 मिनट की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। गुप्ता को कुल 235 महीने जेल में बिताने होंगे। अदालत में निखिल ने अपने किए पर पछतावा जताया और माफी भी मांगी। गौरतलब है कि 55 वर्षीय निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में अपने खिलाफ लगाए गए तीन आरोपों में दोष स्वीकार किया था। इनमें सुपारी देकर हत्या कराने, हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े आरोप शामिल थे। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, मामला 2023 में न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की कथित योजना से जुड़ा है।
गुप्ता को चेक गणराज्य से किया गया था गिरफ्तार- अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गुप्ता ने जिस व्यक्ति से अपराध के लिए संपर्क किया था, उसे वह साजिश में सहयोगी समझ रहा था, लेकिन वह अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) का गोपनीय सूत्र था। जांच आगे बढ़ने पर अमेरिकी एजेंसियों के अंडरकवर अधिकारियों ने भी मामले में भूमिका निभाई और कथित साजिश से जुड़े सबूत जुटाए। गुप्ता को जून 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जून 2024 में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया।

अमेरिका में 90 दिन के ब्लैकआउट की अफवाह, घरों में जमा हो रहा राशन-पानी

चावल, डिब्बाबंद भोजन और पानी की खरीदारी में तेजी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में इन दिनों आम लोग पानी की बोतलें, डिब्बाबंद खाद्य सामग्री, चावल, प्रोपेन गैस और जनरेटर जैसी रोजमर्रा की चीजें भारी मात्रा में खरीदकर घरों में स्टोर कर रहे हैं। इस अचानक बढ़ी खरीदारी के पीछे कोई प्राकृतिक आपदा या तूफान की चेतावनी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही अफवाह है। ऑनलाइन मंचों पर दावा किया जा रहा है कि पूरे देश में अगले 90 दिनों तक बिजली और अन्य आवश्यक सेवाएं पूरी तरह बंद हो सकती हैं।
हालांकि यह दावा पूरी तरह निराधार है, लेकिन लोगों में डर इतना बढ़ गया है कि वॉलमार्ट, कॉस्टको और ट्रैक्टर सप्लाई जैसे प्रमुख रिटेल स्टोरों पर आपातकालीन वस्तुओं की बिक्री में भारी उछाल आया है। वॉलमार्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में प्रोपेन, बोतलबंद पानी और कैंपिंग से जुड़े सामान की मांग कई गुना बढ़ गई, जबकि कॉस्टको में चावल, डिब्बाबंद भोजन और पानी की खरीदारी में तेजी आई है।
इस घबराहट भरी खरीदारी की शुरुआत किसी एक घटना से नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें सितंबर के अंत में जारी अमेरिकी रक्षा विभाग के निर्देश से जुड़ी हैं। सैन्य तैयारियों से संबंधित उस निर्देश को सोशल मीडिया पर तोड़-मरोड़कर 90 दिनों के ब्लैकआउट की चेतावनी के रूप में दिखया गया है। इसके बाद टिकटॉक पर इसरतह के कई फर्जी वीडियो वायरल होने लगे, जिसमें कहा गया कि 17 नवंबर से पूरे अमेरिका की बिजली व्यवस्था ठप्प हो जाएगी। कुछ फर्जी वीडियो में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसी घोषणा करते हुए दिखाया गया था। अमेरिकी आपदा प्रबंधन एजेंसी फेमा द्वारा 17 नवंबर को देशव्यापी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के लिए निर्धारित एक सामान्य परीक्षण को भी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने किसी बड़े संकट का संकेत बताकर अफवाहों से जोड़ दिया।
दूसरी ओर, अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि देशभर में 90 दिनों तक बिजली कटौती की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और इंटरनेट पर वायरल हो रहे ये सभी दावे पूरी तरह झूठे साबित हुए हैं। हालांकि, अफवाहों के इसी दौर में कुछ वास्तविक तकनीकी गड़बड़ियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में रुकावट, हवाई यातायात की संचार प्रणाली में दिक्कत, बैंकिंग कामकाज प्रभावित होना और एप्पल के सॉफ्टवेयर अपडेट में समस्या ने लोगों के संदेह को और गहरा कर दिया। इसके अलावा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और नॉर्वे जैसे देशों में चलाए जा रहे आपातकालीन जागरूकता अभियानों को भी सोशल मीडिया पर अमेरिका में होने वाले ब्लैकआउट के संकेत के तौर पर पेश किया गया, जिससे बेचैनी और बढ़ी। आरबीसी कैपिटल मार्केट्स का मानना है कि यदि भविष्य में कोई नया भू-राजनीतिक तनाव या साइबर हमला सामने आता है, तो लोगों की यह सावधानी घबराहट भरी अंधाधुंध खरीदारी में बदल सकती है।

अमेरिकी चिप युद्ध- पांच देशों पर प्रतिबंध, एआई उद्योग पर मंडराया संकट

वाशिंगटन ,एजेंसी। अमेरिका और चीन के बीच जारी चिप युद्ध अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका ने पांच देशों को एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिप्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका उद्देश्य विदेशी डेटा सेंटरों के माध्यम से चीन को अमेरिकी तकनीक तक पहुंचने से रोकना है। इस कदम से वैश्विक एआई उद्योग में बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
इस नियामक दबाव और संभावित लेखांकन मुद्दों की जांच की खबरों के बीच, चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के शेयर 20 नवंबर को 11.5 प्रतिशत तक गिर गए। रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रतिबंधों से पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बाधित हो सकता है और चीन की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की कोशिशों को बल मिल सकता है। यूएस ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (बीआईएस) ने मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्राजील को भेज जाने वाले एआई चिप्स के लिए निर्यात लाइसेंसिंग की आवश्यकताएं लागू की हैं। यह कार्रवाई मौजूदा निर्यात नियंत्रणों की खामियों को दूर करने के लिए की गई है, जिनके तहत चीनी कंपनियां विदेशी डेटा सेंटरों से अमेरिकी एआई चिप्स तक पहुंच बना रही थीं। अनुमान है कि प्रतिबंध लगने के बावजूद 2024 में लगभग 2.4 लाख एनवीडिया एआई चिप्स चीन भेज गए थे, जिसमें सिंगापुर की मेगास्पीड जैसी कंपनियां अलीबाबा को जीपीयू किराए पर दे रही थीं। ये रोक इसरतह के अप्रत्यक्ष एक्सेस को रोकने के लिए हैं।
सेमीकंडक्टर निर्यात और विदेशी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका की बढ़ती निगरानी से एनवीडिया को भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी का एआई इकोसिस्टम में 61 बिलियन डालर का इक्विटी निवेश और 164.5 बिलियन डालर की लीज़ गारंटी है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में कमी से छोटे क्लाउड प्रदाता प्रभावित होगा, जो उन्नत चिप्स पर निर्भर हैं। इसका असर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कोरवीव पर पहले ही दिख चुका है, जिसके शेयर मूल्य में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है।
इस बीच, चीन अमेरिकी तकनीक पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमताओं को विकसित करने के प्रयासों में तेजी ला रहा है। हाईसिलिकॉन, कैम्ब्रिकॉन और लूंगसन जैसी कंपनियां चिप डिज़ाइन में, एसएमआईसी और हुआ होंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, और नौरा व एएमईसी उपकरण आपूर्ति में सक्रिय हैं। अनुमान है कि 2025 तक चीन का सेमीकंडक्टर उपकरण बाजार 49 बिलियन डालर और सामग्री बाजार 16 बिलियन डालर का होगा, जो घरेलू आपूर्ति-श्रृंखला के विकास की क्षमता को दर्शाता है। यह तकनीकी होड़ एआई के भविष्य और वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दे रही है।

बांग्लादेश में फिर हिंसा, हसीना समर्थकों के 50 घर जलाए

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहीं। नराइल जिले में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के करीब 50 घरों और दुकानों में आग लगा दी गई। घटना कालिया उपजिला के बेंदर चार गांव में हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमले दोपहर से देर रात तक जारी रहे। हमलावरों ने कई घरों में तोडफ़ोड़ की और वहां रखा फर्नीचर, कीमती सामान और दूसरी चीजें लूट लीं। पूर्व पीएम शेख हसीना देश लौटने की बात कह चुकी हैं। इसके बाद से ही तनाव बढ़ गया है। बीते दिनों हुई हिंसा में पीएम तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी के दो नेताओं की हत्या हुई थी। स्थानीय लोगों ने इन हमलों के लिए पीएम तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया है। हालांकि, हमले में शामिल लोगों की पहचान नहीं हुई। पूर्व अवामी लीग सांसद बीएम कबीरुल हक मुक्ति बिस्वास का पुश्तैनी घर भी जला दिया गया है।

क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले का रुस ने लिया बदला, यूक्रेन पर दागे ड्रोन व मिसाइलें

हमले में आठ की मौत, कई पुल, बिजली-पानी सप्लाई और रेलवे को पहुंचा नुकसान

कीव, एजेंसी। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले का बदला ले लिया। यूक्रेन पर रुस ने 400 से ज्यादा ड्रोन और 110 से ज्यादा मिसाइलें दागीं। इस हमले में आठ लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने हमले में 27 बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इसे युद्ध के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया। हमले में कई पुलों, बिजली-पानी की सप्लाई और रेलवे को नुकसान पहुंचा है।
बता दें इससे पहले गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज पर हमले पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि रूस इस हमले का दर्दनाक जवाब देगा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने बताया कि हमले में मारे गए आठ लोगों में से 6 कीव के रहने वाले थे। बाकी 2 लोगों की मौत पश्चिमी शहर लवीव के एक रेलवे स्टेशन पर हुई। रातभर हुए हमलों में कीव में कई धमाके हुए। जान बचाने के लिए लोग मेट्रो स्टेशनों में छिप गए। रूस ने निप्रो नदी पर बने कीव के 3 पुलों को भी निशाना बनाया। सरकार ने लोगों से अपील की कि वे कार से काम पर जाने से बचें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने हमले की रणनीति ऐसी बनाई थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा तबाही हो। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने क्लस्टर वारहेड वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों में एक बड़े बम से कई छोटे बम निकलते हैं, जो बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं। जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने मिसाइलें एक साथ दागने के बजाय कई समूहों में छोड़ीं। हर हमले के बीच 20 से 30 मिनट का अंतर रखा। इससे राहत और बचाव टीमों को काम करने में मुश्किल हुई। वे आग बुझाने, मलबा हटाने और बिजली-पानी जैसी जरूरी सेवाएं बहाल करने में जुटी थीं। उन्होंने कहा कि पुतिन ने यह हमला बेहद सोच-समझकर और दिखावे के तौर पर किया। जेलेंस्की ने चीन में हुई बैठकों को कमजोर बताया और कहा कि दुनिया की व्यवस्था को अपने हिसाब से बदलने की रूस

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मणिपुर में जहरीली शराब पीने से 15 की मौत, तीन लोगों की हालत गंभीर

- 600 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती, इस साल 6 राज्यों में 120 की जा चुकी है जान

इंफाल , एजेंसी। मणिपुर के चंदेल जिले में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 2 से 3 दिनों में यह मामला सामने आया है। लोगों की तबीयत शराब पीने के बाद बिगड़ी। हालांकि शराब कहां से लाई गई थी, इसकी सही जानकारी उनके पास नहीं है। साल 2026 में जहरीली शराब पीने से मध्यप्रदेश, गुजरात समेत 6 राज्यों में 120 से ज्यादा लोग जान गवां चुके हैं। पुलिस के मुताबिक प्रभावित लोगों ने जो शराब पी थी, उसे मणिपुर के काकचिंग जिले के सुगनू से खरीदा गया था। जांच में शराब में मेथनॉल मिलाए जाने की आशंका है। इस मामले में अब तक करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चंदेल जिले में स्थानीय स्तर पर शराब बनाने की कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में आशंका है कि दूसरे इलाकों से शराब लाकर यहां बेची गई थी। पुलिस शराब सप्लाई करने वालों की तलाश कर रही है।

मेटा कार्यालयों पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन : तोड़फोड़, हंगामा और एफआईआर

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) ने हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) के कार्यालयों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम खातों को 19 नवंबर को निलंबित करने के विरोध में था। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा के कहने पर हुई थी। संगठन ने सात दिनों के भीतर खातों को बहाल करने की मांग की थी, अन्यथा देशभर में प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। हैदराबाद में प्रदर्शनकारी कार्यालय के अंदर घुस गए, जहां तोड़फोड़ कर एक गमला को तोड़ दिया गया। पुलिस ने तेलंगाना यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जक्किडी शिव चरण रेड्डी के नेतृत्व में 20-21 कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया, हालांकि करीब तीन घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। मुंबई में, कार्यकर्ताओं ने बिल्डिंग के शीशे पर आरएसएस का बेटा मेटा का नारा लिखा, जिससे शीशे को नुकसान पहुंचा। यहीं प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय आईटी और सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का पोस्टर भी जलाया। मुंबई पुलिस ने मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जीना सबरीन सहित चार लोगों और 15-20 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 और महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1995 की धारा 3 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं के मेटा कार्यालयों पर पहुंचने के 15 मिनट के भीतर निलंबित खाते बहाल किए गए। संगठन ने सवाल उठाया कि ये खाते किसके आदेश पर निलंबित किए गए थे और क्या भारतीयों को अपनी आवाज उठाने के लिए हमेशा मेटा कार्यालयों का रुख करना होगा।

सांसद अमृतपाल दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पैतृक गांव पहुंचे

अमृतसर , एजेंसी। पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह शनिवार को अमृतसर स्थित अपने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा पहुंचे हैं। वे अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं। पुलिस उन्हें बुलेटप्रूफ गाड़ी में अमृतसर एयरपोर्ट से लाई और पिछले रास्ते से निकाला। अमृतसर कोर्ट से अमृतपाल को शनिवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, कुल तीन घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है। इस दौरान उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई गई। अमृतपाल की दादी का निधन 8 नवंबर को हुआ था, लेकिन परिवार ने उनके आने तक अंतिम संस्कार रोक रखा था।

केंद्रीय मंत्री रिजिजू का राहुल गांधी पर पलटवार, 1962 युद्ध पर कांग्रेस से माफी की मांग

एपीईसी का सदस्य नहीं भारत, राहुल गांधी को इतना भी नहीं पता

नई दिल्ली , एजेंसी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के कम्प्रोमाइज्ड पीएम वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने राहुल गांधी से चार तीखे सवाल पूछे और 1962 के भारत-चीन युद्ध, देश में गरीबी तथा पिछली आर्थिक स्थिति के लिए कांग्रेस से माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।



दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर कहा था कि एक कम्प्रोमाइज्ड पीएम कभी वैश्विक नेताओं की उस मेज पर नहीं बैठ सकता। यह बयान राहुल द्वारा साझा की गई 19 नवंबर 2026 की एक तस्वीर के बाद आया, जिसमें चीन के शेनझेन में हुए एपीईसी शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ बैठे दिख रहे थे। इस तस्वीर को पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तब भारत के प्रधानमंत्री इस मेज पर होते। हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत एपेक का सदस्य नहीं है। इस त्रिपक्षीय बैठक में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और यूक्रेन व ईरान के संघर्षों पर चर्चा हुई थी।

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बताकर कांग्रेस से अतीत की गलतियों का हिसाब मांगा। उनके रुख का समर्थन करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने भी राहुल गांधी से सवाल किया। राष्ट्रीय महासचिव संतोष ने कहा कि 1947 से 1977, 1980 से 1989, 1991 से 1996 और 2004 से 2014 तक कांग्रेस सत्ता में थी और कई बार भारी बहुमत भी था, तब यूएनएससी सहित किन बड़े वैश्विक मंचों पर भारत उस दौरान बैठा था?

राहुल गांधी ने पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों, खासकर नोटबंदी और जीएसटी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन कदमों ने छोटे व्यापारियों को बर्बाद किया है और बड़ी कंपनियों के लिए मैदान साफ कर दिया है, इससे देश में कारोबार के क्षेत्र में एकाधिकार बढ़ा है। राहुल गांधी के मुताबिक, एकाधिकार से कीमतें बढ़ती हैं और प्रतिस्पर्धा खत्म होती है, जिससे नौकरियां पैदा नहीं होतीं। पीएम मोदी ने इससे पहले कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बावजूद कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की सैलरी और संख्या न बढ़ाने पर सवाल उठाया था।

सीएम योगी की मां का हरिद्वार में हुआ अंतिम संस्कार, छोटे भाई ने दी मुखाग्नि

- सीएम धामी, बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद हुए शामिल, शुक्रवार को हुआ था निधन

हरिद्वार, एजेंसी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का अंतिम संस्कार हरिद्वार के चंडीघाट पर किया गया। सीएम योगी के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। इस दौरान यहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद सरस्वती और अन्य लोग मौजूद थे। बता दें योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को पौड़ी गढ़वाल जिले में उनके पैतृक गांव पंचूर में निधन हो गया था। वह पिछले काफी समय से बीमार थीं। सावित्री देवी के परिवार में चार बेटे और तीन बेटियां हैं। आदित्यनाथ, चारों बेटों में दूसरे स्थान पर हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी के बड़े भाई मानवेंद्र सिंह बिष्ट और सबसे छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट गांव के निकट बिथ्याणी महाविद्यालय में कार्यरत हैं जबकि एक अन्य छोटे भाई शैलेंद्र मोहन बिष्ट भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल में ऑर्डिनरी कैप्टन हैं। सीएम योगी की एक बहन पुष्पा चौधरी दिल्ली में और दूसरी बहन कौशल्या देवी कोटद्वार में रहती हैं जबकि तीसरी बहन शशि पायल ऋषिकेश के निकट स्थित प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर के पास व्यवसाय करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस गहरे दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। बाबा रामदेव ने कहा कि आदरणीय माता सावित्री देवी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया है और ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। हम उन्हें केवल एक साधारण माता के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र की माता के रूप में देखते हैं।

देश, धर्म और संविधान की रक्षा के लिए सनातनियों को एकजुट होना होगा: धीरेंद्र शास्त्री

- मणिपुर की जातीय हिंसा में अब तक कम से कम 306 की जा चुकी है जान

प्रतापगढ़, एजेंसी। कथा वायक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कुंडा में चल रही राम कथा के समापन के अवसर पर हिंदू एकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश, धर्म और संविधान की रक्षा के लिए सनातनियों को एकजुट होना होगा। इस दौरान शास्त्री ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। शास्त्री ने कहा कि देखिए, यह इस देश और हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू का ही विरोध करता है, क्योंकि हिंदू काफी दब्बू होते हैं और पलटकर जवाब नहीं देते लेकिन कुंडा से हिंदुओं ने पलटकर जवाब देना सीख लिया है कि अब अगर आप हमें उकसाएंगे, तो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह तय है, अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा की रक्षा के लिए सभी को एक मंच पर आना होगा। जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटने के बजाय एकता को ही सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। उन्होंने युवाओं से भी धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने की अपील की। हिंदू एकता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग हिंदू एकता से डरते हैं। वे सनातन एकता से डरते हैं। कुछ लोग अपनी जाति-आधारित राजनीति साधना चाहते हैं, इसलिए उनके मन में कहीं न कहीं कुंठा भरी होती है और जो कुंठित रहता है, वह बैकुंठ नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को बांटकर राजनीति करते हैं, वे अंत में खुद ही कमजोर हो जाते हैं। एकता ही सनातन की असली पहचान है। अखिलेश यादव से जुड़े सवाल पर शास्त्री ने कहा कि हम सभी दलों के हैं, एक गुरु सबका होता है क्योंकि अगर कोई गुरु सिर्फ एक व्यक्ति का हो जाए, तो वह फिर गुरु नहीं रहता। सूरज सबका होता है और उसी तरह एक गुरु भी सबका होता है। अभी हम पंजाब में एक कथा करने जा रहे हैं।

विदेशी नागरिक होने के बावजूद मारुति कंपनी में 50 फीसदी की थी हिस्सेदार

बीजेपी सांसद ने मारुति परियोजना को लेकर सोनिया गांधी पर उठाए सवाल

नई दिल्ली , एजेंसी । बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मारुति परियोजना को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सवाल उठाए। अपनी सोशल मीडिया सीरीज कांग्रेस का काला अध्याय की 250वीं कड़ी में उन्होंने दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी 1970 के दशक में मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एमटीएस) की निदेशक और 50 फीसदी हिस्सेदार थीं। दुबे ने आरोप लगाया कि तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की सरकार ने गांधी परिवार से जुड़ी कंपनी को कई तरह की सरकारी सुविधाएं दीं।



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबे ने दावा किया कि 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि कंपनी को 1968 में ही कार बनाने की अनुमति कैसे मिल गई, जबकि एमटीएस का गठन नवंबर 1970 में हुआ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 1969 में इंदिरा गांधी की कैबिनेट ने संजय गांधी की कार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए विशेष आदेश जारी किया था।

दुबे ने हरियाणा में मारुति परियोजना के लिए जमीन आवंटन पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि उस समय के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी। उन्होंने 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी गांधी परिवार से जुड़ी कंपनियों को कर्ज उपलब्ध कराने के आरोप से जोड़ा। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के चालू होने से पहले ही राज्य सरकारों से बस बॉडी बनाने के लिए एडवांस भुगतान कराया गया और सरकारी कंपनियों ने बिना भुगतान सीमेंट, स्टील तथा कोयले की आपूर्ति की।

मारुति विवाद से जुड़ा एक अहम तथ्य 22 अप्रैल 1975 को लोकसभा में दिए गए तत्कालीन सरकारी जवाब में भी दर्ज है। इसमें कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड के हवाले से कहा गया था कि सोनिया गांधी कभी मारुति लिमिटेड की निदेशक नहीं रहीं। हालांकि, यह जवाब मारुति लिमिटेड के बारे में था, न कि मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में. दोनों कंपनियों को एक समझना सही नहीं होगा।

दुबे ने अपनी पोस्ट के आखिर में सोनिया गांधी से मारुति परियोजना और उससे जुड़ी कंपनियों के गठन, हिस्सेदारी तथा सरकारी मदद को लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि गांधी परिवार ने निजी निवेश के बिना इतना बड़ा कारोबारी उपक्रम कैसे खड़ा किया।

कोटा से 8 साल बाद पाकिस्तान के लिए सिख जत्था रवाना, बिरला के प्रयासों से मिला वीजा

कोटा ,एजेंसी। लगभग आठ साल के लंबे इंतजार के बाद, कोटा के 12 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष प्रयासों से इन श्रद्धालुओं को पाकिस्तान का वीजा मिल सका। शुक्रवार सुबह सभी श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर मेल से अमृतसर के लिए रवाना हुए। कोटा रेलवे स्टेशन पर महापौर अनसुइया गोस्वामी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दीं। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि वर्षों से अधूरी एक भावना को भी पूरा करने का अवसर है। श्रद्धालुओं ने बताया कि अंतिम बार वर्ष 2019 में कोटा से सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान गया था। इसके बाद कोरोना महामारी और सोसायटी के तत्कालीन प्रधान के निधन के कारण पाकिस्तान यात्रा के लिए आवश्यक प्रक्रिया और विभागीय औपचारिकताओं की जानकारी के अभाव में जत्थे का जाना बंद हो गया था।

अगर पीओके भारत में वापस आता है यह भू-राजनीतिक और आर्थिक मायनों में गेमचेंजर होगा

चीन को लगेगा झटका, सीपीईसी ड्रैगन की परियोजना अपने आप ठप हो जाएगी

नई दिल्ली , एजेंसी। अगर पाकिस्तान के कब्जे वाला पीआके भारत में वापस आ जाता है, तो यह भारत के लिए सिर्फ एक क्षेत्रीय वापसी नहीं होगी, बल्कि कई भू-राजनीतिक और आर्थिक मायनों में एक गेमचेंजर साबित होगी। पीओके की घरवापसी भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक ऐसा शॉर्टकट होगा, जो न केवल ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमारी मौजूदा निर्भरता को खत्म कर देगा, बल्कि चीन के सबसे महत्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को भी करारा झटका देगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप तक अपना सामान पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर का लंबा और महंगा रास्ता अपनाना पड़ता है। पाकिस्तान द्वारा पीओके पर अवैध कब्जे के कारण, भारत का सेंट्रल एशिया से सीधा जमीनी संपर्क पूरी तरह कटा हुआ है। नतीजतन, भारत को इन देशों से व्यापार करने के लिए मुंबई या गुजरात के बंदरगाहों से पहले समुद्र के रास्ते ईरान के बंदर अब्बास तक जहाज भेजने पड़ते हैं, और वहां से ट्रेन और ट्रकों के जरिए ईरान और अफगानिस्तान होते हुए सामान सेंट्रल एशिया तक जाता है। यह रास्ता लंबा, महंगा होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अमेरिकी प्रतिबंधों और क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात के कारण अक्सर बाधित होता रहता है।

अगर पीओके खासकर इसका उत्तरी हिस्सा यानी गिलगित-बाल्टिस्तान, वापस भारत के पास आ जाता है, तो यह पूरी तस्वीर बदल देगा। गिलगित-बाल्टिस्तान की सीमा सीधे अफगानिस्तान के उस पतले से हिस्से से लगती है, जिसे वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। यह कॉरिडोर एक संकरी पट्टी है जो एक तरफ ताजिकिस्तान यानी सेंट्रल एशिया को छूती है और दूसरी तरफ चीन को। पीओके की वापसी से भारत को सीधे वाखान कॉरिडोर तक पहुंच मिल जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि भारत बिना पाकिस्तान की जमीन पर पैर रखे और बिना ईरान के समुद्र का चक्कर लगाए, सीधे सड़क और रेल के जरिए ताजिकिस्तान में दाखिल हो सकेगा। वहां से पूरे सेंट्रल एशिया और आगे रूस व यूरोप तक का सड़क नेटवर्क पहले से मौजूद है।

सेंट्रल एशियाई देश प्राकृतिक गैस, तेल, यूरेनियम और लिथियम जैसे दुर्लभ खनिजों के मामले में बेहद समृद्ध हैं। सीधा जमीनी रास्ता खुलने के बाद भारत सीधे पाइपलाइन या रेल टैंकरों के जरिए सेंट्रल एशिया से तेल और गैस मंगा सकेगा, जिससे खाड़ी देशों पर भारत की ऊर्जा निर्भरता कम होगी। रणनीतिक लिहाज से पीओके की घरवापसी का सबसे बड़ा झटका चीन को लगेगा। चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके सीपीईसी बनाया है, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। जिस दिन यह इलाका वापस भारत के कंट्रोल में आएगा, चीन का यह ड्रीम प्रोजेक्ट अपने आप ठप हो जाएगा और भारत सेंट्रल एशिया में चीन की दादागीरी को सीधी चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगा।



हम प्रेशर ग्रुप ही बने रहना चाहते हैं, राजनीतिक दल बनने में कोई दिलचस्पी नहीं

सीजेपी नेता सौरभ दास का दावा-बीजेपी के कुछ समर्थक भी अब पार्टी से परेशान

नई दिल्ली , एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सौरभ दास ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ मतदाता भी अब पार्टी से परेशान हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस संबंध में एक किस्सा भी साझा किया। सौरभ दास फिलहाल यूपी में सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। पार्टी ने अभी तक किसी नए बड़े प्रदर्शन का ऐलान नहीं किया है। जब सौरभ दास से पूछा गया कि क्या बीजेपी के मतदाता भी सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा होते हुए देखा है। पॉडकास्ट में सौरभ ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल सीजेपी को एक राजनीतिक दल बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अभी एक प्रेशर ग्रुप ही बने रहना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जब वे सड़क पर चलते हैं, तो कई लोग उनके पास आकर तारीफ करते हैं और फिर अंत में कहते हैं कि वे वैसे तो बीजेपी के समर्थक थे, लेकिन अब नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने एक बीजेपी समर्थक से मिलने का



अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में दिवाली पार्टी में एक व्यक्ति ने उन्हें पहचाना और उनके साथ फोटो खिंचवाई। उस व्यक्ति ने कहा कि वह बीजेपी समर्थक है, लेकिन बहुत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कर दिया है इन लोगों ने। सौरभ दास ने कहा कि वे इन फैन सिटर्स को बीजेपी के विरोध में होते हुए देख रहे हैं।

उन्होंने बीजेपी के मतदाताओं पर भी सवाल उठाए, विशेष रूप से मॉडरेट वोटर्स पर। उन्होंने कहा कि वे उन चरमपंथी मतदाताओं की बात नहीं कर रहे हैं जो एकदम ही ब्रेन वॉश हो गए हैं। उनका मानना है कि ऐसे लोगों को सच या वास्तविकता दिखाना कभी-कभी एक निराशाजनक खेल लगता है। उन्होंने इन मतदाताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि एक्यूआई 3000 प्लस होने के बावजूद वे कहते हैं कि पटाखे फोड़िए, क्योंकि इससे एक्यूआई में कोई फर्क नहीं पड़ता। दास ने स्वीकार किया कि ऐसे लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, उन्हें इसका जवाब नहीं पता। सौरभ दास ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि वह उत्तर प्रदेश के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं।

बता दें यूपी में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव होंगे। सीजेपी ने हाल ही में अपनी टीम का विस्तार किया है और यूपी, महाराष्ट्र, बिहार समेत 10 ज़ोन में टीमों का ऐलान किया है, जिसमें सबसे बड़ी टीम यूपी में उतारी गई है।

पूर्व एम्स डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप, शादी का झांसा दे किया यौन शोषण

पटना, एजेंसी । पटना एम्स के पूर्व जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर सतन कुमार पर 28 वर्षीय युवती ने शादी का झांसा देकर तीन साल तक यौन शोषण और दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि डॉक्टर ने उस नशीला पदार्थ खिलाकर पहली बार दुष्कर्म किया, फिर शादी का वादा कर संबंध बनाता रहा। गर्भवती होने पर डॉक्टर ने उसका जबरन गर्भपात भी कराया और बाद में शादी से साफ इंकार किया। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, बिहटा निवासी पीड़िता का हाथ जलने के बाद वह इलाज के लिए पटना एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग पहुंची थी, जहाँ उसकी पहचान तत्कालीन जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर सतन कुमार से हुई। पीड़िता का कहना है कि दिसंबर 2022 में डॉक्टर ने मुझे इलाज के बहाने एम्स परिसर स्थित बॉयज हॉस्टल के कमरा नंबर 313 में बुलाया। वहां आरोपी सनत कुमार ने चाय-नाश्ते में नशीला पदार्थ दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने खुद को अस्त-व्यस्त पाया और डॉक्टर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।

चक्रवाती तूफान अकवान के बाद आएगा कानी, मालदीव ने सुझाया नाम

नई दिल्ली, एजेंसी । बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान अकवान के बाद अगला चक्रवाती तूफान कौन-सा होगा और उसका नाम क्या रखा गया है। इस तरह के सवाल लोगों के मन दस्तक देने लगे है हालांकि आने वाले चक्रवाती तूफान अकवान को लेकर तटीय राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चक्रवातों के नामकरण की निर्धारित सूची के अनुसार, अकवान के बाद आने वाले तूफान का नाम कानी होगा। यह नाम मालदीव ने सुझाया है। उत्तरी हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफानों के नामकरण के लिए 13 देशों की सूची तैयार की गई है। इसी सूची में ईरान की ओर से सुझाया गया अकवान नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद अगला नाम मालदीव का सुझाया हुआ कानी होगा। स्थानीय भाषा में कानी का अर्थ सुंदर युवती या युवा व्यक्ति बताया जाता है। कानी के बाद सूची में म्यांमार का सुझाया नाम नगामन आएगा। कानी तूफान के आने की फिलहाल कोई निश्चित तारीख नहीं है। मौसम विभाग ने अभी तक इस नाम से किसी नए चक्रवाती तूफान के बनने की चेतावनी जारी नहीं की है। दरअसल, चक्रवातों का निर्माण समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने, समुद्री सतह के तापमान और हवा की अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर



करता है। जब किसी मौसमी सिस्टम की हवा की रफ्तार कम से कम 62 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, तब उसे चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखकर आधिकारिक नाम दिया जाता है। नवंबर और दिसंबर का समय पोस्ट-मानसून सीजन होने के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफानों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के तहत गठित पैनल करता है। इस पैनल में भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन सहित 13 देश शामिल हैं। इन देशों ने वर्ष 2020 में 13-13 नामों की सूची तैयार की थी। इस तरह कुल 169 नाम तय किए गए हैं। इन नामों का इस्तेमाल क्रमवार किया जाता है।